



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 23, 2018/कार्तिक 1, 1940

No. 344]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2018/KARTIKA 1, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2018

अंतिम जांच परिणाम

(मामला संख्या ओआई-42/2017)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, जर्मनी और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डि मेथिल फोर्मेमाईड" (डीएमएफ) के आयातों संबंधित पाटन-रोधी शुल्क की जांच।

1. फा. संख्या 6/37/2017-डीजीएडी.—यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मेसर्स बालाजी अमीन्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' अथवा 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने चीन जनवादी गणराज्य, जर्मनी और सऊदी अरब (जिसे आगे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डि मेथिल फोर्मेमाईड" (डीएमएफ) के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. यतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22.01.2018 की अधिसूचना संख्या 6/37/2017-डीजीएडी जारी की थी, जिसके द्वारा उपरोक्त नियमावली के उप-नियम 5 के अनुसार पाटन-रोधी जांच शुरू की गई थी, ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. क्रिया-विधि

3. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के संबंध में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

(i) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन-पत्र के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों दूतावासों को अधिसूचित किया था।

(ii) प्राधिकारी ने प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध आयातों की पाटन-रोधी निर्णायक जांच समीक्षा शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 22.01.2018 को प्रकाशित अधिसूचना जारी की थी।

(iii) नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे संबद्ध देशों में निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें।

(iv) नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां प्रेषित की थीं:-

1. मेथानोल केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब
2. फहाद थान्यान अल थन्यान एंड पीए, सऊदी अरब
3. बारविल एजेंसीज लिमिटेड, सऊदी अरब
4. केबोकमे एजी, जर्मनी
5. टेमिनको बीवीबीए, जर्मनी
6. शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
7. हुआलू होलिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
8. जिबो लुझोंग फाईन केमिकल एंड लाईट इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
9. अन्हुल हुआईहुआ फाईन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
10. झेझियांग जिआंगशान केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(v) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेथानोल केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब
2. मेसर्ज लूक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
3. मेसर्ज शॉनडोंग लिओचेंग लूक्सी न्यू मेटेरियल सेल कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
4. मेसर्ज लूक्सी केमिकल (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
5. शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(vi) बाजार अर्थव्यवस्था पर एक अनुपूरक प्रश्नावली भी भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास और चीन जनवादी गणराज्य में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबद्ध सूचना प्रेषित कर दें।

(vii) चीन जनवादी गणराज्य से उत्पादकों/निर्यातकों ने केवल निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य के गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश होने की अवधारणा का खंडन करने वाली प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) का कोई पर्याप्त दावा नहीं किए जाने के स्थिति में वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

(viii) नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

1. मेसर्ज आर्चिड केमिकल्स एंड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड
2. मेसर्ज सिमड लैब्स लिमिटेड
3. मेसर्ज मेटेरिक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड

4. मेसर्ज डोर्फ-केटल केमिकल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5. मेसर्ज हरमान फिंकोकेम लिमिटेड
6. मेसर्ज रामकमल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
7. मेसर्ज पिरामल इंटरप्राइजिज लिमिटेड
8. मेसर्ज मेट्रिक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड
9. मेसर्ज एएमआई आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
10. मेसर्ज इंडियन एंक्रेलिक्स लिमिटेड
11. मेसर्ज बोकहार्ड्ट लिमिटेड
12. मेसर्ज योगेश डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13. मेसर्ज सन फार्मेक्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
14. मेसर्ज ल्यूपिन लिमिटेड
15. मेसर्ज अरोबिन्दो फार्मा लिमिटेड

(ix) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज इंडियन एंक्रेलिक्स लिमिटेड
2. मेसर्ज अरोबिन्दो फार्मा लिमिटेड
3. मेसर्ज पशुपति एंक्रिलोन लिमिटेड
4. मेसर्ज रामकमल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5. मेसर्ज अमी आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
6. मेसर्ज लौरस लैब लिमिटेड

(x) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध कराया था।

(xi) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई थी। जांच के प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक समझा गया था, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन किया गया था।

(xii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उसे सार्वजनिक फाईल में रखा गया था।

(xiii) भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और उनको निर्मित करने और बेचने के आधार पर क्षति रहित कीमत का सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और आकलन किया गया है, ताकि क्षति मार्जिन का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xiv) याचिका द्वितीयक स्रोत के आयात आंकड़ों (इम्पोर्ट जीनियस) के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। प्राधिकारी ने उसकी जांच की थी और उन्होंने जांच शुरू करने के लिए पाटन और क्षति होने के पर्याप्त साक्ष्य पाए थे। याचिका के एक भाग के रूप में इम्पोर्ट जीनियस को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में रखा गया था। जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया था कि वह क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने की व्यवस्था करें। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में विभिन्न प्राचलों का विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

(xv) जांच 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान की गई थी। क्षति की जांच करने की अवधि में अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015, अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017 और जांच अवधि को भी शामिल किया गया है।

(xvi) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए 04.05.2018 को एक मौखिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में 11.05.2018 तक और उसके बाद उनके उत्तर 18.05.2018 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें।

(xvii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों का निदान इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है। संबद्ध देशों/संघों/परिसंघों/अवस्थापनाओं द्वारा किए गए निवेदनों पर विधिवत् विचार किया गया है और उनका उचित निदान किया गया है।

(xviii) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।

(xix) हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 28.09.2018 को प्रकटन विवरण जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचारार्थ अनिवार्य तथ्य निहित थे। हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण पर यदि कोई टिप्पणी प्रस्तुत करनी है, तो उसके लिए 09.10.2018 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने प्रकटन पश्चात् हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुई टिप्पणियों पर उचित रूप से विचार किया है।

(xx) हितबद्ध पक्षकार द्वारा *** सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।

(xxi) इस जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 66.53 रूपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र और "समान वस्तु"

4. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "डि मेथिल फोर्मेमाईड" (डीएमएफ) है। यह एक वर्णहीन हाई ब्यालिंग पोलर एप्रोटिक विलायक है, जिसका लक्षण गंध है। यह हीटिंग और उसकी डिस्टिलिएशन तापमान सीमा पर स्थिर है और यह जल, अल्कोहल, ईथर, किटोन्स, ईस्टर, कार्बन डिसुल्फाईड और क्लोरिनेटिड और एरोमेटिक हाईड्रोकार्बन्स के साथ स्वतंत्र रूप से मिश्रणीय है।

5. संबद्ध वस्तुओं का व्यापक रूप से उपयोग निम्नोक्त श्रेणियों के लिए किया जा सकता है:-

- (क) फार्मेस्युटिकल विनिर्माण में विलायक के रूप में
- (ख) एक्रेलिक पालिमर्स विनिर्माण में विलायक के रूप में
- (ग) डीएमएफ के डेरिवेटिव्स के सिंथेसिस के लिए एक फीडबैक के रूप में
- (घ) पेस्टीसाईड्स फार्म्युलेशन्स में एक विलायक के रूप में

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 में विशिष्ट एचएस संहिता संख्या 2921 1110 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त एचएस संहिताएं निर्देशात्मक मात्र मानी जाती हैं और ये सभी परिस्थितियों में उत्पादन विवरण निर्णायक हैं।

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों में उत्पादित और वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भौतिक विशेषता, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में ये दोनों उत्पाद तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं और वे इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं।

8. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और उसके दायरे के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

9. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि मेसर्ज बालाजी अमीन्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तुओं का अकेली उत्पादक कंपनी है और इसलिए उनका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100% भाग बनता है। मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक कंपनी थी, लेकिन कुछ समय से उसने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करना बंद कर दिया है और मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड ने वर्तमान जांच में सहायता करने का एक समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है। मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड याचिकादाता के इस तर्क का समर्थन करती है कि यदि संबद्ध वस्तुओं पर शीघ्र पाटन-रोधी शुल्क नहीं लागू किए जाते हैं, तो पाटन के कारण मेसर्ज बालाजी अमीन्स लिमिटेड का डीएमएफ संयंत्र भी बंद हो सकता है।

10. निर्यातक/आयातक ने निवेदन किया है कि मेसर्ज राष्ट्रीय केमिकल्स एक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने दिनांक 31.05.2018 के पत्र द्वारा वर्तमान जांच का समर्थन किया है, हालांकि उनका कोई आधार नहीं है। उनका यह निवेदन प्रासंगिक नहीं है कि पाटित आयातों और अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण आरसीएफ को नुकसान हुआ है और इस पर इसलिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरसीएफ ने क्षति विश्लेषण अवधि अथवा जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया है। समान वस्तु की उत्पादन क्षमताएं होने मात्र से घरेलू उद्योग की अवश्यता पूरी नहीं होती हैं। मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड के संबंध में याचिकादाता के पास कोई संक्षिप्त विवरण नहीं है। मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड के प्रचालनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने और आरसीएफ से कोई संक्षिप्त विवरण प्राप्त किए बिना बयान दिया गया है। याचिकादाता इसकी गारंटी नहीं दे सकता है कि मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड डीएमएफ का उत्पादन करना शुरू करेगी। ऐसे समस्त दावों को पूर्णतया खारिज कर दिया जाना चाहिए।

11. प्राधिकारी ने मेसर्ज बालाजी अमीन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र की जांच की है, जो कि इस समय वर्तमान में संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है। मेसर्ज राष्ट्रीय केमिकल्स एक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक अन्य उत्पादक ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है। मेसर्ज बालाजी अमीन्स लिमिटेड ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है।

12. यह नोट किया जाता है कि पात्र घरेलू उद्योग के रूप में याचिकादाता के दावे के प्रतिवाद में कोई निवेदन नहीं किया गया है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू करने के बाद मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड द्वारा वर्तमान जांच का समर्थन करने को भी नोट किया है, जिसके लिए कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का कोई उत्पादन नहीं किया है और उसको घरेलू उद्योग के रूप में अभिज्ञात करने का कोई आधार नहीं है।

13. प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि इस समय याचिकादाता का कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सा 100% है और वह नियमावली के 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग बनता है तथा वह उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार आधार के मानदंड को भी पूरा करता है।

घ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

14. याचिकादाता ने बताया है कि उसने कुछ सूचना की गोपनीयता का दावा किया है और मात्रा के प्राचलों का प्रकटन किया है, जिससे प्रतिवादी पक्षकार मामले को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन वर्तमान मामले में निर्यातकों/आयातकों ने मात्रा संबंधी सूचना भी प्रकट नहीं की है और गोपनीयता के अत्यधिक दावों को छिपाने के लिए आवेदक के खिलाफ अत्यधिक गोपनीयता बरतने का आरोप लगाया है जो कि सही नहीं है। प्रतिवादी पक्षकारों को कम से कम निर्यात/आयात की अपनी वास्तविक मात्रा की सीमा का प्रकट करना चाहिए, ताकि याचिकादाता भी प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर अपनी टिप्पणियां दे सके।

15. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ने कोई कानूनी कारण बताए बिना अधिकतर सूचना को गोपनीय रखा है और ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्यातक को अपनी प्रभावी टिप्पणियां दे कर अपने हितों की रक्षा करने के लिए निवेदन करने के उचित अवसर से वंचित रखा गया है। याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त से उसमें निहित आरोपों को उचित रूप से समझा नहीं जा सकता है। याचिकादाता को अपने दावे के औचित्य को दर्शाने की आवश्यकता है, लेकिन वह कार्यशील पूंजी का परिकलन, आवधिक ऋणों पर ब्याज, मूल्यह्रास, वर्ष के दौरान अर्जित विविध आय के व्यौरों, जांच अवधि के शुरू होने और अंत में डब्ल्यूआईपी के व्यौरों पर उत्तर देने में विफल रहा है। मेसर्ज बालाजी अमीन्स लिमिटेड जैसी बहु-व्यवसायिक कंपनी में प्रत्येक भाग में विभिन्न उत्पादों के लिए वार्षिक रिपोर्टें समेकित की जाती हैं और ऐसी समेकित वित्तीय सूचना को प्राप्त करना और उसे विचाराधीन उत्पाद के साथ जोड़ना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त कारोबार-वार आयात के आंकड़े भी एक्सिस फार्म में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

16. प्राधिकारी ने निवेदनों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य को प्रदत्त किए गए सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल में भी उपलब्ध कराया गया था, जिसमें नियम 6 (7) के अनुसार जांच के लिए विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय वृत्तान्त निहित था।

17. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की जांच, उनके दावों के औचित्य और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विशिष्ट प्रावधानों के संबंध में की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और तदनुसार उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

18. कारोबार-वार और छांटे गए आयात आंकड़ों के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात के करोबार-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 07/2018 के अनुसार प्राधिकारी से आंकड़े प्राप्त कर सकता है।

ड. विविध मुद्दे

घरेलू उद्योग के निवेदन

19. विविध मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. कुछ पक्षकारों के इस यह तर्क की कोई मेरिट नहीं है कि याचिका साक्ष्यात्मक और कानूनी मानकों को पूरा नहीं करती है। याचिका में विभिन्न दावों की संपुष्टि करने के लिए विश्वसनीय और पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए याचिकादाता ने श्रेष्ठ संभव प्रयास किए थे। यहां तक कि निर्यात कीमत से समायोजन करने के अनुमानों को श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया था और विधि के अंतर्गत ऐसी कार्य-प्रणालियों की अनुमति है तथा याचिका में ऐसी प्रत्येक सूचना प्रदान की गई है, जिस पर विश्वास किया गया है। प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि याचिकादाता ने याचिका में सही साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने श्रेष्ठ सामर्थ्य का उपयोग किया है और अन्यथा दावे किसी मेरिट के बिना होते।
- ii. यह तर्क दिया गया है कि मेसर्ज बालाजी द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क लगा हुआ है। इस समय डीएमसी पर पाटन-रोधी शुल्क लगा हुआ है और डीएमसी का उत्पादन मेसर्ज बालाजी और मेसर्ज आरसीएफ लिमिटेड द्वारा किया जाता है। मेसर्ज बालाजी द्वारा उत्पादित मोरफोलाईन नामक उत्पाद पर पहले से शुल्क लागू थे और बाद में उन्हें हटा दिया गया था/कोई निर्णायक समीक्षा जांच शुरू नहीं की गई थी। कंपनी कुछ उत्पादों पर अच्छा कार्य कर रही है, जो कि डीएमएफ में क्षति को अस्वीकार नहीं करती है।
- iii. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त आयात आंकड़ों का संज्ञान नहीं लिया है और उक्त आंकड़ों का विलोपन बहुत बड़ी गलती है तथा ऐसा आयात में विशाल उछाल दर्शाने के लिए किया गया था। इस तर्क का कोई आधार नहीं है और गलती आंकड़ों के एक सेट पर आरोपित की गई है, जिसका उपयोग एक वैध कारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है। जब याचिका दायर की गई थी, डीजीसीआईएंडएस के संक्षिप्त आयात आंकड़े पूरी जांच अवधि के लिए उपलब्ध नहीं थे और जांच अवधि को छोड़ कर कुछ वर्षों के लिए उनका प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तब घरेलू उद्योग ने द्वितीयक स्रोत के अनुसार टी/टी आंकड़े मंगाए थे ताकि समग्र जांच अवधि के लिए सही आयात आंकड़े सुनिश्चित किए जा सकें। टी/टी आंकड़ों में यह नोट किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद के आयात अभीष्ट वर्गीकरण से इतर विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत किए गए थे और साथ ही यह भी नोट किया गया था कि कुछ अन्य उत्पाद डीएमएफ के लिए अभीष्ट वर्गीकरण के अंतर्गत भी किए गए थे ताकि डीजीसीआईएंडएस के संक्षिप्त आयात आंकड़ों पर विश्वसनीयता को पूरी तरह से नकारा जा सके। घरेलू उद्योग के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए बहुत विश्वसनीय आंकड़ों का प्रयोग करे। यह दोहराया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस के संक्षिप्त आंकड़ों में अशुद्धताएं हैं, जो कि वर्तमान मामले में उक्त आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं बनाती है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार के आरोप में कोई मेरिट नहीं है और यह घरेलू उद्योग के गलत कार्य को इंगित करने के लिए किया गया था, जिसमें कोई मेरिट नहीं है।
- iv. वर्तमान मामले के तथ्य आर्थिक क्षति के स्पष्ट मामले को दर्शाते हैं। कंपनी ने कुछ वर्ष पहले अपना उत्पादन शुरू किया था, लेकिन वह जांच की वर्तमान अवधि तक विभिन्न प्राचलों पर कार्य-निष्पादन के मामूली स्तर तक ही पहुंच सकी थी।

प्रतिवादी पक्षकारों के निवेदन

20. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- i. याचिकादाता ने ऐसा कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो कि पाटन-रोधी जांच की शुरुआत को प्रमाणित कर सके, जबकि जांच प्राधिकारी ने संबंधित तथ्यों की पर्याप्त संवीक्षा करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई नहीं की है। पाटन, क्षति तथा आरोपित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के बारे में याचिका साक्ष्य परक और कानूनी मानकों को पूरा नहीं करती है।
- ii. याचिका में याचिकादाता द्वारा सूचित आंकड़ों की मात्रा, डीजीसीआईएंडएस के अनुसार स्वतः अभीष्ट वर्गीकरण के अंतर्गत सूचित किए गए आंकड़ों की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, यदि अन्य वर्गीकरणों में सूचित आयातों का उल्लेख नहीं किया जाए। इससे याचिका में निहित सूचना की परिशुद्धता पर बहुत प्रतिकूल होने का स्पष्ट पता चलता है। याचिका में सूचित आंकड़ों की मात्रा और अभीष्ट वर्गीकरण के अंतर्गत सूचित आयातों की मात्रा के बीच अंतर की प्रकृति स्वतः इतनी भिन्न है कि उससे सूचना की परिशुद्धता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। जैसा कि गुआटेमाला - सीमेंट-2 के मामले में विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्णय दिया गया है, जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ साक्ष्य की पर्याप्तता, वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती है।
- iii. मेसर्स बालाजी अमीन्स लिमिटेड नामक याचिकादाता द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होने से व्यापारिक उपचार उपायों के वेश में अत्यधिक संरक्षण प्राप्त करने की प्रवृत्ति का पता चलता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. विविध निवेदनों की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

- i. जांच शुरू करने के आरोप के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन-पत्र में किए गए विभिन्न दावों पर उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- ii. यह एक सुस्थापित पद्धति है कि जांच की कार्रवाई के दौरान सूचना की गुणवत्ता और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसमें सुधार होता है।
- iii. इस निवेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने याचिका प्रस्तुत करते समय डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त आयात आंकड़ों का संज्ञान नहीं लिया था, यह नोट किया जाता है कि याचिकादाता ने एक्सपोर्ट जीनियस नाम द्वितीयक स्रोत में सूचित आयात आंकड़ों पर विश्वास किया था। याचिकादाता ने दावा किया था कि द्वितीयक स्रोत के आंकड़े इस कारणवश प्रयुक्त किए गए थे कि विचाराधीन उत्पाद के अभीष्ट सीमा-शुल्क वर्गीकरण की आठ अंकीय स्तर संहिता होने के बावजूद विभिन्न अन्य उप-शीर्षों के अंतर्गत उसके आयात किए जा रहे हैं। उस समय प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करना पर्याप्त समझा गया था।
- iv. जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी ने जांच अवधि और विगत तीन वर्षों के लिए डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं। वर्तमान मामले में डीजीसीआईएंडएस से टी/टी आयात आंकड़ों का उपयोग देश में आयात की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया गया है। यह नोट किया जाता है कि समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए याचिका द्वारा विश्वास किए गए द्वितीयक स्रोत के आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की बीच व्यापक अंतर व्याप्त है। याचिका में सूचित आंकड़ों की मात्रा और डीजीसीआईएंडएस में सूचित आयातों की मात्रा में इस प्रकार का अंतर, जिसमें चौंकाने वाली भिन्नता है, निश्चित रूप से याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत सूचना की परिशुद्धता और याचिकादाता द्वारा दावा की गई क्षति की प्रवृत्तियों के बारे में सन्देह उत्पन्न करता है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य से उत्पादकों/निर्यातकों ने संबद्ध अनुपूरक प्रश्नावली के प्रपत्र में उत्तर दे कर एनएमई की पूर्वधारणा का खंडन नहीं किया है। चीन में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ii. उचित लाभ के लिए समायोजित याचिकादाता के उत्पादन की लागत के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य उपयुक्त कार्य-प्रणाली होगी और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे वर्तमान मामले में भी उक्त उपागम को अपनाएं। ऐसी श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना जर्मनी के लिए भी लागू होगी चूंकि जर्मनी से उत्पादकों/निर्यातकों से भी कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है।

- iii. याचिका में विश्वास किए गए आयात आंकड़े द्वितीयक स्रोत की सूचना पर आधारित थे। ऐसी सूचना की एक प्रति सार्वजनिक फाईल में भी उपलब्ध कराई गई थी। आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन अत्यधिक है और यह घरेलू उद्योग की आर्थिक क्षति का कारण है।
- iv. भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात संबद्ध देशों से उनके सामान्य मूल्यों से कम मूल्य पर किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।
- v. सऊदी अरब से मेसर्स मेथानोल केमिकल कंपनी ने वर्तमान मामले में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इस पक्षकार के निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जा सकता है कि कंपनी घाटों पर है और डीएमएफ उसके निर्यातों और समग्र राजस्व का प्रमुख भाग बनाता है। घरेलू उद्योग को इस बड़े निर्यातक के निर्यातों के कारण पहले से हुई क्षति के अतिरिक्त स्पष्टतः और गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उक्त निर्यातक की निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में यह निवेदन किया गया है कि उसका किसी पक्षकार के साथ गैस की आपूर्ति करने का करार हुआ है तथा उस पक्षकार का नाम अथवा करार के ब्यौरे याचिकादाता को प्रकट नहीं किए गए हैं। यह अनुरोध है कि प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 के अनुसार निर्यातक के उत्पादन की लागत कड़ी संवीक्षा करें ताकि यह देखा जाए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यातक की लागत, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के साथ सहयोजित लागत को प्रतिबिंबित करती है।
- vi. कुछ पक्षकारों ने याचिकादाता द्वारा दावा किए गए आधार अथवा सामान्य मूल्य के मामले को उठाया है और तर्क दिया है कि वर्तमान जांच में चीन में निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को सऊदी अरब की सूचना पर विचार करना चाहिए। चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातकों के पास एनएमई की पूर्वधारणा का खंडन करने का अवसर था, जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया है। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य के लिए अनुबंध-1 का पैरा 7 प्रासंगिक है। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के लिए सीएनवी विधि का सुसंगत रूप से अनुसरण किया है और वर्तमान मामले में भी उन्हें इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चीन जनवादी गणराज्य और सऊदी अरब में आर्थिक दशाओं के बीच कोई साम्यता नहीं है तथा चीन जनवादी गणराज्य के लिए एक उचित प्रतिनियुक्त देश के रूप में सऊदी अरब पर विचार करने का कोई कानूनी और वास्तविक आधार नहीं है।
- vii. प्रतिवादी पक्षकारों ने निवेदन किए हैं कि सीएनवी के प्रयोजनार्थ उच्च लागत के प्रभाव से बचने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग का समयोजन किया जाना चाहिए। पाटित आयातों के कारण कम क्षमता उपयोग हुआ था तथा सीएनवी और अन्य प्रयोजनों के लिए केवल वास्तविक ब्यौरों के अनुसार घरेलू उद्योग की लागत पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे निर्यातक जिन्होंने पाटन की पद्धति अपना कर घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति पहुंचाई है, अब यह तर्क देते हैं कि कुछ अवास्तविक रूप से निम्न सीएनवी का आक्कलन किया जाना चाहिए ताकि निर्यातक निर्दोष ठहराए जा सकें।

प्रतिवादी पक्षकारों के विचार

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. चीन जनवादी गणराज्य से उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला माना जाना कानूनी प्रावधानों से असंगत है, इसलिए चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना विवेकाधीन है, जिसके फलस्वरूप पाटन मार्जिन निर्धारण त्रुटिपूर्ण हो जाता है। वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य से कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उनकी घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर किया जाए। चीन में निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त कोई भी अन्य कार्य-प्रणाली विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत के दायित्वों का उल्लंघन होगी।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा आवदेन-पत्र में चीन में उत्पादकों के लिए संरचित सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत पर आधारित है और इसमें लाभ की दर 5% मानी गई है। तथापि, संरचित सामान्य मूल्य की मद-वार लागत के ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए हैं।
- iii. याचिकादाता ने सामान्य मूल्य की संरचना के लिए आवश्यक किसी भी अन्य दशा के विद्यमान होने को प्रमाणित नहीं किया है। संबद्ध प्रावधानों में सामान्य मूल्य की संरचना के लिए एक आधार के रूप में घरेलू बिक्री कीमतों से संबंधित आंकड़ों की "अनुपलब्धता" का उल्लेख नहीं है।
- iv. ऐसे संबद्ध देशों के लिए जो कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, सामान्य मूल्य एक मात्र धारा 9 क (1) के स्पष्टीकरण (ग) पर आधारित होना चाहिए। उक्त स्पष्टीकरण में घरेलू उद्योग की निजी लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने की अनुमति नहीं देता है।

- v. जांच शुरू करने की सूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या ऐसे "प्रथम दृष्ट्या" मुद्दों और असंगतियों की जांच की गई थी अथवा नहीं। जबकि सत्य यह है कि प्रतिवादियों द्वारा प्रदत्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। ऐसे उपागम से जांच शुरू करने के लिए प्रारंभिक साक्ष्यात्मक आधार से संबंधित प्रावधान अनावश्यक हो जाते हैं।
- vi. आवेदन-पत्र के एनसीवी में निबल निर्यात कीमत में दावा की गई कटौतियों से संबंधित कोई साक्ष्य निहित नहीं है। इसके अतिरिक्त अंतरदेशीय भाड़े और पत्तन हैंडलिंग प्रभारों का उत्पाद की कीमत से कोई संबंध नहीं है। इसलिए सीआईएफ अथवा एफओबी के प्रतिशत के रूप में इन व्ययों का परिकलन करने का उक्त आधार गलत है। प्रत्येक समंजन के संबंध में याचिका में प्रस्तुत किया गया आंकड़ा दृढ़ कथन मात्र है, जो कि साक्ष्यों से अप्रमाणित है, जिस पर मामला शुरू करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- vii. यहां तक कि याचिकादाता निर्यातक देश के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों, सभी संबद्ध देशों में समान सामान्य मूल्य को प्रक्षेपित करने और निर्यात कीमत से भत्तों के लिए अप्रमाणित कटौतियों के बारे में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं रहा है।
- viii. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर विचारित सामान्य मूल्य सही नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत विकृत है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल के स्रोत का पता लगाना भी एक समस्या है क्योंकि वह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयातों पर विश्वास करता है, इसलिए उत्पादन की लागत और भी अधिक हो जाती है। याचिकादाता के आंकड़ों के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य को अपनाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसने बहुत अधिक सीमा तक उत्पादन की क्षमताओं का उपयोग नहीं किया है। याचिकादाता की परिवर्तन लागतें अप्राकृतिक रूप से बहुत अधिक और अविश्वसनीय हैं, जो कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उचित लागतों को निरूपित नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे कम क्षमता उपयोग के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- ix. सामान्य मूल्य का परिकलन घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है जो कि स्वतः बड़ी हुई है। निर्यात कीमत के आंकड़े द्वितीयक स्रोत के आंकड़ों पर आधारित हैं, जो कि सही नहीं हैं। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा यथा परिकलित पाटन मार्जिन विकृत है और यह विश्वसनीय नहीं है।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया क्षमता उपयोग, उपयोग के स्तर से काफी कम है जिसे ऐसे संयंत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अनुरोध है कि याचिकादाता की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसमें प्राप्त किए गए अनुकूलतम क्षमता उपयोग पर विचार किया जाए। चीन के लिए सीएनवी का निर्धारण, प्रोजेक्ट की अर्थक्षमता रिपोर्ट में यथा प्रक्षेपित अनुकूलतम संयंत्र उपयोग के स्तरों पर विचार करते हुए किया जाए।
- xi. याचिकादाता ने बताया है कि उसने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र (चीन जनवादी गणराज्य को छोड़ कर जिसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है) में कीमत संबंधी कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।
- xii. याचिकादाता ने सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए आवश्यकता के लिए कोई विद्यमान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। संबद्ध प्रावधानों में सामान्य मूल्य की संरचना के लिए एक आधार के रूप में घरेलू बिक्री कीमतों से संबंधित आंकड़ों की "अनुपलब्धता" का उल्लेख नहीं है।
- xiii. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे वर्तमान जांच में चीन में निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सऊदी अरब से प्राप्त सूचना पर विचार करें। विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रति यूनिट निर्धारित लागत, वास्तविक निर्धारित लागत से लगभग 3-4 गुना अधिक है। इसलिए अनुरोध है कि ऐसे आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना मूलतः त्रुटिपूर्ण है और यह चीन से निर्यातों के खिलाफ पाटन का मामला बनाने के प्रयोजन से कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई है, जबकि वास्तव में पाटन विद्यमान नहीं है।
- xiv. पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग का यह दायित्व है कि वह कोई अनुचित विलंब किए बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीयक देश के बारे सूचित करने ताकि संबंधित पक्षकारों को उस पर उत्तर देने का एक अवसर मिल सके।
- xv. वर्तमान जांच में शामिल सभी संबद्ध देशों के लिए जिनमें चीन शामिल नहीं है, आवेदन-पत्र में सामान्य मूल्य "संरचित" किया गया है जो कि घरेलू उद्योग की निजी कीमतों और लागतों पर आधारित है। यहां तक कि घरेलू उद्योग का ऐसा "प्रथम दृष्ट्या" उपागम सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए धारा 9 क (1) के स्पष्टीकरण (ग) में दिए गए प्रावधान को पूरा नहीं करता है। ऐसे संबद्ध देशों के लिए जो कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, सामान्य मूल्य एक मात्र धारा 9 क (1) के स्पष्टीकरण (ग) पर आधारित होना चाहिए। उक्त स्पष्टीकरण में घरेलू उद्योग की निजी लागतों

के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने की अनुमति नहीं देता है। मेसर्ज बाल सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनी निजी कार्य-प्रणाली नहीं बना सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. चीन जनवादी गणराज्य और सऊदी अरब से निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं और सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में निवेदन किए हैं। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी पक्षकार ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था के निरूपण का दावा किया है। इसके अतिरिक्त जर्मनी से किसी भी निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

- i. मेसर्ज शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)
- ii. मेसर्ज लूक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड कोर-अल्कली केमिकल ब्रांच, चीन (उत्पादक) के साथ और उसके निर्यातक और व्यापारी, मेसर्ज शॉनडोंग लियाचुंग लूक्सी न्यू मेटेरियल सेल कंपनी लिमिटेड और मेसर्ज लूक्सी केमिकल (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड
- iii. मेसर्ज मेथानोल केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब

25. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

I. चीन जनवादी गणराज्य

(1) सामान्य मूल्य

26. जांच शुरू किए जाने के चरण में याचिकादाताओं ने चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने की पूर्वधारणा से आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी थी कि वे जांच शुरू करने की सूचना का उत्तर दें और यह निर्धारित करने के लिए संबद्ध सूचना प्रदान करें कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अपनाया जा सकता है। इस संबंध में संबद्ध सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकारी ने प्रश्नावली की प्रतियां सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रेषित की थीं। चीन में निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दिए थे, लेकिन किसी ने भी बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण की प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और चीन की सरकार को निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से सूचना प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था और उन्हें इस संबंध में पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया था। चूंकि किसी भी उत्पादक ने एमईटी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी यह उपयुक्त समझते हैं कि वर्तमान जांच में चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और चीन जनवादी गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए चीन जनवादी गणराज्य से आयातित संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य की संरचना, कच्चे माल और प्रयोज्यताओं, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि के लिए घरेलू उद्योग के लिए स्वीकृत सभी स्तरों पर घरेलू उद्योग के अनुकूलतम खपत मानकों को ध्यान में रख कर की गई है, जिसमें उचित लाभ शामिल है।

(2) निर्यात कीमत

(क) मेसर्ज लूक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, मेसर्ज क्लोर अल्कली केमिकल ब्रांच (उत्पादक), मेसर्ज लियाचेंग लूक्सी न्यू मेटेरियल सेल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) और मेसर्ज लूक्सी केमिकल (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

29. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मेसर्ज लूक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित व्यापारियों, मेसर्ज लियाचेंग लूक्सी न्यू मेटेरियल सेल कंपनी लिमिटेड और मेसर्ज लूक्सी केमिकल (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन प्रभारों और बैंक प्रभारों के कारण किए गए समायोजनों के दावे किए गए हैं और प्राधिकारी ने कारखाना-गत स्तर पर निर्यात कीमत के परिकलन के लिए उनकी अनुमति दे दी है। भारत को निर्यातों के लिए निर्धारित निबल निर्यात कीमत, नीचे पाटन तालिका में दर्शाई गई है।

(ख) मेसर्ज शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड

30. मेसर्ज शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। यह नोट किया जाता है कि मेसर्ज शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक कंपनी होने के साथ-साथ एक निर्यातक भी है। जांच अवधि के दौरान मेसर्ज शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत को सीधे

निर्यात किए हैं। उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन प्रभारों और बैंक प्रभारों के कारण किए गए समायोजनों के दावे किए गए हैं और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार, मेसर्ज शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए कारखाना-गत स्तर पर निर्यात कीमत आक्कलित की गई है। भारत को निर्यातों के लिए निर्धारित निबल निर्यात कीमत, नीचे पाटन तालिका में दर्शाई गई है।

II. जर्मनी

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जर्मनी से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए रिकार्ड पर उपलब्ध श्रेष्ठ तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, नीचे पाटन तालिका में दर्शाया गया है।

III. सऊदी अरब

(क) मेसर्ज मेथानाल केमिकल्स कंपनी

(1) सामान्य मूल्य

32. मेसर्ज मेथानाल केमिकल्स कंपनी ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इसकी जांच की गई है और यह पाया गया है कि संबद्ध वस्तुओं की घरेलू विक्रियां, उत्पादक-निर्यातक की कुल विक्रियों के 5% से भी कम हैं और इसलिए वे पर्याप्तता के परीक्षण को पूरा नहीं करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने उनके लिए उपलब्ध श्रेष्ठ तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है।

(2) निर्यात कीमत

33. मेसर्ज मेथानाल केमिकल्स कंपनी ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। यह नोट किया जाता है कि वे संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के साथ-साथ निर्यातक भी हैं। जांच अवधि के दौरान मेसर्ज मेथानाल केमिकल्स कंपनी ने सीधे भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। भारतीय उपभोक्ताओं को ये विक्रियां एफओबी आधार पर की जाती हैं। मेसर्ज मेथानाल केमिकल्स कंपनी के लिए अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन प्रभारों और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन करने के दावे किए गए हैं और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार, मेसर्ज मेथानाल केमिकल्स कंपनी के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत आक्कलन किया गया है। भारत में निर्यातों के लिए निर्धारित की गई निबल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

IV. पाटन मार्जिन

34. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना-गत स्तर पर सामान्य मूल्य और निबल निर्यात कीमत के साथ तुलना करके किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	उत्पादक/निर्यातक	सीएनवी	एनएफपी	डीएम		
		अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	%	सीमा
1	शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	***	***	***	***	20-30
2	लूक्सी केमिकल ग्रुप कोर सिलकली केमिकल ब्रांच/ शॉनडोंग लियाचुंग लूक्सी न्यू मेटेरियल सेल कंपनी लिमिटेड/ लूक्सी केमिकल (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	***	***	***	***	35-45
3	मेथानाल केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब	***	***	***	***	25-35
4	जर्मनी	***	***	***	***	35-45

ज. क्षति मूल्यांकन के लिए कार्य-प्रणाली तथा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

घरेलू उद्योग के विचार

35. वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से अत्यधिक पाटन हो रहा है। अनेक वर्षों से ऐसे पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पृथक रूप से संबद्ध देशों से आयात 3% से अधिक हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब से सर्वाधिक आयात हो रहे हैं। पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है और ये मांग में लगभग 84% बाजार के हिस्से के धारक हैं, जो कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के किसी भी विशिष्ट व्यापन को रोके हुए है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान लगभग 15% मात्र हिस्से को ही प्राप्त कर सका है और बाकी समस्त हिस्सा पाटित आयातों ने धारण कर लिया है। तृतीय देश के आयात नगण्य हैं।
- ii. ऐसे आयातों की पाटित कीमतें, सकारात्मक कीमत कटौती के स्तर पर थीं। ऐसी कीमत कटौती के क्षति के कीमत प्राचलों पर बहुताधिक प्रभाव पड़े थे, जो कि आगे चल कर लाभ, आरओआई आदि के रूप में समान स्थिति पर प्रक्षेपण से पता चलता है।
- iii. कीमत में कटौती के अत्यधिक स्तर द्वारा रोकी गई कीमत में वृद्धि का लाभप्रदता और आरओआई पर प्रपाती प्रभाव पड़े हैं और वास्तव में लाभप्रदता बहुत निम्न स्तर पर बनी हुई है तथा आरओआई भी निम्न एकल अंकीय स्तर पर बनी हुई है, जिससे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई अत्यधिक आर्थिक क्षति का पता चलता है।
- iv. घरेलू उद्योग के मात्रा के स्तर सामान्य अथवा बहुत नगण्य स्तरों पर बने हुए हैं, जो कि उसकी बहुत कम उत्पादन मात्रा, सम मूल्य क्षमता से कम उपयोग और बिक्रियों की कम मात्रा से पता चलता है और ऐसी सम मूल्य की मात्रा की स्थिति तब है, जब कि मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह पाटित आयातों के स्पष्ट प्रभाव को दर्शाती है।
- v. मात्रा और मूल्य प्राचलों दोनों के निष्पादन में कमी होने से विकट पाटन और परिणामी आर्थिक क्षति का पता चलता है। घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है, जैसा कि संबद्ध देशों से पाटन के कारण नियम में परिकल्पित है।
- vi. यह कहना बहुत काल्पनिक है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान जबकि मांग लगभग 42277 मी.टन थी, बिक्रियों में वृद्धि होना उचित संवृद्धि है। जांच अवधि में वास्तविक मात्रा स्वतः प्रासंगिक है और पाटन में लगे हुए निर्यातक, यह कहते हुए कि प्रवृत्ति के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है, उसके बाजार के हिस्से में वृद्धि का उदाहरण दे कर, घरेलू उद्योग द्वारा आधार वर्ष में की गई कम बिक्रियों का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- vii. उत्पादन के संबंध में आयातों का हिस्सा गिरावट दर्शा सकता है, लेकिन ऐसा आधार वर्ष में उत्पादन की कम मात्रा के कारण हुआ है। यह ऐसा नहीं दर्शाता है कि जांच अवधि सहित पाटित आयातों के स्तर में कोई विशेष संवृद्धि नहीं हुई है।
- viii. घरेलू उद्योग ने कुछ उचित स्तर पर घरेलू मांग का कोई भी लाभ उठाने से पहले से ही किनारा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप कम उत्पादन और बिक्रियां होने से स्पष्ट पता चलता है कि उसे ऐसे पाटित आयातों के कारण मात्रात्मक क्षति हुई है।
- ix. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की औसत कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है। पाटित आयातों की मात्रा को बनाए रखने और घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अधिक आपूर्ति करने से दूर रखने के लिए निर्यातकों ने कीमत में कटौतियां की थीं। घरेलू उद्योग विशिष्ट ऊंचे स्तर पर कीमतों को बढ़ा सकता था ताकि वह उचित लाभ अर्जित कर सके, लेकिन पाटित आयातों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, जो कि कीमतों में अत्यधिक कटौती होने के स्तर पर उपलब्ध थे। वर्तमान मामले में कीमत क्षति दृष्टव्य है।
- x. कीमत हास/अत्यधिक स्तर पर कीमतों में वृद्धि की रोकथाम का इस तथ्य से स्पष्ट पता चलता है कि एनएसआर लगभग वही बना रहा है और लागत में गिरावट आई है। लागत में गिरावट के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होने की गुंजाईश पर पाटित आयातों द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- xi. समस्त क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में स्थापित क्षमता वही बनी रही है और वह भारतीय मांग को अत्यधिक भाग को पूरा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है।
- xii. जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग स्पष्ट रूप से समता स्तर से नीचे है और यह संबद्ध देशों से पाटित आयातों के अत्यधिक स्तर का प्रत्यक्ष परिणाम है। घरेलू उद्योग ने कम से कम 5 वर्ष लिए थे और इस पूरे समय में पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण क्षमता के बेहतर उपयोग में अडचन आई है।
- xiii. पाटन ने घरेलू उद्योग को अधिक उत्पादन और बिक्री करने से रोका है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियों ने कुछ वृद्धि दर्शाई है, हालांकि यह बहुत कम स्तर पर थी। इस प्रकार जांच अवधि के दौरान इस कारक से आर्थिक क्षति स्वतः ऐसी निम्न उत्पादन मात्रा से दृष्टव्य है, जबकि मांग बहुत मजबूत थी। पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग को उत्पादन को गणनीय स्तर पर बढ़ाने में सहायक होगा।

- xiv. विक्रियों की कम मात्रा होने का कारण अत्यधिक सकारात्मक कीमत-कटौती स्तरों पर पाटित आयात होना है, जिससे आर्थिक क्षति की विकट स्थिति का विशिष्ट रूप से पता चलता है।
- xv. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास बहुत अधिक मालसूचियां थीं। मालसूचियों का इतना अधिक स्तर तब था जब कि देश में उत्पाद की मांग ने अत्यधिक संवृद्धि दर्ज की थी। मालसूची के स्तर से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं पर पाटित आयातों के दबाव का स्पष्ट पता चलता है।
- xvi. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए लाभ और आरओआई ऐसे लाभ को नहीं दर्शाता है, जो कि पाटन नहीं होने की स्थिति में प्राप्त किया जा सकता था। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक लाभ और आरओआई अत्यधिक थे, लेकिन ये उससे कम थे, जो कि घरेलू उद्योग पाटन नहीं होने की स्थिति में अर्जित कर सकता था।
- xvii. रोजगार का स्तर भी उत्पादन की प्रवृत्ति को दर्शाता है और उद्योग के पास अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है, यदि उद्योग अधिक उत्पादन और विक्री करने की स्थिति में होता। जांच अवधि के दौरान उत्पादकता अच्छे स्तरों पर थी और उत्पादकता में किसी भी प्रकार की कोई कमी क्षति का कारण नहीं थी। लागत में वेतनों के संघटक ने भी समग्र लागत की प्रवृत्ति को दर्शाया है और वास्तव में वेतनों में वृद्धि क्षति का कारण नहीं थी।
- xviii. हालांकि अनेक वर्षों से कम स्तरों पर उत्पादन होने के बाद भी उद्योग की मंद संवृद्धि में आर्थिक क्षति प्रतिबिंबित होती है।
- xix. घरेलू उद्योग ने क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए संबद्ध सूचना भी प्रदान की है और यह देखा जाएगा कि आयातों का पहुंच मूल्य, स्पष्टतया क्षति रहित कीमत से कम था, जिसके फलस्वरूप वर्तमान मामले में सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।
- xx. याचिका में प्रस्तुत किया गया गैर-आरोपण विश्लेषण संबद्ध देशों से पाटन और उसके कारण हुई घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को स्पष्ट दर्शाता है। पाटन ने घरेलू उद्योग के बेहतर कार्य-निष्पादन को रोका है और यह वर्तमान मामले में पाटन और आर्थिक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने को प्रमाणित करता है।
- xxi. हालांकि सभी प्राचलों में गिरावट, पाटन रोधी करार में यथा वर्णित आर्थिक क्षति को नहीं दर्शा सकती है और इसलिए आर्थिक क्षति का निर्धारण, मात्र प्रवृत्ति विश्लेषण की तुलना में अधिक सार्थक विश्लेषण होना चाहिए। स्वतः जांच अवधि के दौरान विभिन्न प्राचलों की वास्तविक स्थिति पर बल देते हुए वर्तमान मामले में विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो कि आर्थिक क्षति को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर घरेलू उद्योग के समान कम कार्य-निष्पादन को दर्शाएगा। जांच अवधि में निर्धारित प्राचलों पर कार्य-निष्पादन को विवेकपूर्ण स्तर पर प्राप्त नहीं करना भी आर्थिक क्षति को दर्शाता है, जांच अवधि में भले ही उसमें समझेदी संवृत्ति में वृद्धि हुई हो। यह स्थिति वर्तमान मामले में क्षति के लगभग प्रत्येक प्राचल पर लागू होती है।
- xxii. वर्तमान मामले में आर्थिक क्षति इस तथ्य में दृष्टव्य है कि जांच अवधि के दौरान पाटन होने के फलस्वरूप मात्रा और कीमत दोनों के प्राचल मंद स्तर पर और सामान्य स्तर से कम पर बने हुए हैं और इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग पाटन के ऐसे क्षतिजनक प्रभाव को समाप्त करने के लिए पाटन-रोधी शुल्क लागू किए बिना अधिक समय तक सुस्थिर नहीं रह सकता है। स्वतः जांच अवधि के दौरान पाटन के कारण मंद कार्य-निष्पादन, वर्तमान मामले में जांच अवधि के दौरान आर्थिक क्षति का सूचक है तथा इससे मात्रा और कीमत दोनों प्राचलों में साम्य से कम कार्य-निष्पादन का पता चलता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है और प्रतिकूल दावों में मेरिट की कमी है।
- xxiii. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई लाभप्रदता उससे कम है जो कि वह पाटन नहीं होने की स्थिति में प्राप्त कर सकता था और यह 22% आरओआई से भी कम है, जिसे प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत के प्रयोजनार्थ प्रतिलाभ का उचित स्तर माना जाता है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग आधार वर्ष में नकारात्मक स्थिति से जांच अवधि के दौरान निम्न एकल अंकीय आरओआई को ही प्राप्त कर सका है और घरेलू उद्योग का ऐसा मंद कार्य-निष्पादन उसकी आर्थिक क्षति को दर्शाता है। आधार वर्ष की तुलना में सुधार, जांच अवधि में साम्य कार्य-निष्पादन से कम स्तर पर होने से व्यर्थ हो जाता है और जांच अवधि में कार्य-निष्पादन आर्थिक क्षति की स्थिति को दर्शाता है।
- xxiv. यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग की डीएमएफ की स्थापित क्षमता 30000 मी.टन है और यह 75% भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह बाजार में पाटित आयातों के फलस्वरूप 15% से भी कम विक्री कर सका है।

प्रतिवादी पक्षकारों के विचार

36. वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान क्षति के संबंध में प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है क्योंकि सभी संबद्ध आर्थिक प्राचल अत्यधिक सुधार दर्शाते हैं।
- ii. घरेलू उद्योग को कोई मात्रा और कीमत क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने आरोपित पाटित आयातों और आरोपित आर्थिक क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध को प्रमाणित नहीं किया है। पाटित आयातों और आर्थिक क्षति के बीच किसी कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करने के लिए अनुबंध-2 के दोनों पैराओं (2) और (4) में उल्लिखित दशाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में न तो पैरा (2) में उल्लिखित दशाओं को और न ही पैरा (4) में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में प्रदत्त क्षति के साक्ष्य का अनुशीलन मात्र करने से किसी भी दशा का स्पष्ट पता नहीं चलता है।
- iii. निर्धारित अवधि में किसी भी समय लक्षित देशों से आयातों ने याचिकादाता की बिक्रियों पर किसी भी प्रकार का कोई मात्रात्मक दबाव नहीं डाला है। संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना घरेलू बाजार की खपत के साथ करने पर उसमें विकट कमी आई है, जो स्पष्ट करता है कि संबद्ध देशों से आयातों का कोई मात्रात्मक दबाव नहीं पड़ा है।
- iv. सकारात्मक कीमत कटौती होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपने कार्य-निष्पादन में सुधार किया है। इसलिए वर्तमान मामले में कीमत कटौती प्रासंगिक नहीं है। संबद्ध देशों से आयातों ने संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों को प्रभावित नहीं किया था।
- v. विश्वभर में बिक्रियों की लागत में कमी होने के समनुरूप पहुंच मूल्य में भी गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें बढ़ती रही हैं। इसलिए पहुंच मूल्य और घरेलू बिक्री कीमत के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- vi. याचिकादाता कंपनी ने मांग के आंकड़ों को कम बताया है। याचिकादाता ने वास्तव में यह बताया है कि आयात अन्य सीमा-शुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी हो रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि याचिका अत्यधिक गलत आंकड़ों पर आधारित है और उसमें आंकड़ों की परिशुद्धता और पर्याप्तता की कमी है।
- vii. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में देखने से मालसूचियों में गिरावट का पता चलता है क्योंकि मालसूचियों में वृद्धि उत्पादन और बिक्रियों के समनुरूप नहीं है। परिणाम स्वरूप नकदी लाभ में वृद्धि हुई है। नकदी प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। समग्र क्षति विश्लेषण अवधि में कर पूर्व लाभ और समग्र लाभ भी बढ़ा है। घरेलू उद्योग द्वारा सृजित रोजगार में भी बहुविध वृद्धि हुई है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, अदा किए गए वेतनों, उत्पादता प्रति कर्मचारी और उत्पादकता प्रति दिन में बढ़ोतरी हुई है। आधार वर्ष में निवेश पर नकारात्मक प्रतिलाभ था, जबकि जांच अवधि में उसमें सकारात्मक वृद्धि हुई है और यह अत्यधिक वृद्धि है। यह भी देखा जा सकता है कि अलग-अलग वर्ष के आधार पर घरेलू उद्योग की सुसंगत संवृद्धि हुई है। घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करने पर पता चलता है कि जबकि बिक्रियों की लागत में कमी आई है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु की बिक्री कीमत बढ़ गई है। इसलिए संबद्ध देशों से आयात, संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं।
- viii. अनुबंध-2 के पैरा (4) में निर्धारित 15 आर्थिक प्राचलों का समग्र विश्लेषण करने से स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग के प्राचलों में अत्यधिक सुधार हुआ है और संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डाला है क्योंकि कोई भी अकेला संबद्ध आर्थिक कारक, पैरा (4) में उल्लिखित नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। समग्र क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग निरंतर लाभ अर्जित कर रहा है और जांच अवधि के दौरान उसने सर्वाधिक लाभ अर्जित किया है। यदि याचिकादाता पहले से ही पूंजी पर 22% प्रतिलाभ अर्जित कर रहा है, तो उसे क्षति होने का मामला कैसे बनता है।
- ix. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों से क्षति हुई है। इस प्रकार पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध होने की संभावना समाप्त हो जाती है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातों का बढ़ा-चढ़ा कर उल्लेख किया है और जानबूझ कर घरेलू उद्योग की क्षति कल्पित की है।
- x. याचिकादाता द्वारा स्थापित क्षमता स्पष्ट नहीं है। याचिकादाता के पास विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की 18,000 मी.टन क्षमता है, लेकिन उसने अपनी याचिका में 30,000 मी.टन क्षमता होने का दावा किया है। यह 42,473 मी.टन मांग की तुलना में बहुत कम है। याचिकादाता इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा है, जिससे कि घरेलू उद्योग की मांग पूरी हो सके। निचले स्तर के भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए भारत में संबद्ध

देशों से उत्पादों के आयात किए जा रहे हैं। संबद्ध वस्तुओं के आयात केवल ऐसी मांग को पूरा करने के लिए किए जाते हैं और न कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए।

- xi. हालांकि सऊदी अरब से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, उसके बाजार के हिस्से में घोर कमी आई है। बाजार के निम्न हिस्से का तात्पर्य उत्पाद को बेचने के लिए अधिक प्रयास करने पर भी कम विक्रियां होने से है। वास्तव में आयातों में वृद्धि, घरेलू उद्योग पर पाटन के परिणामी प्रभाव को दर्शाने का कारक नहीं है।
- xii. घरेलू उद्योग का वित्तीय विवरण जांच अवधि में कंपनी द्वारा अर्जित अच्छे लाभ को दर्शाता है, जो कि उसको क्षति होने के उसके अपने दावे को खंडित करता है।
- xiii. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भी कर रहा है, लेकिन ऐसी सूचना की गोपनीयता का दावा किया गया है।
- xiv. कम कीमत पर बिक्री होना, घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाला एक कारक नहीं माना जा सकता है। क्षति मार्जिन और कम कीमत पर बिक्री का प्रश्न केवल तब उठता है, जब प्राधिकारी का यह निष्कर्ष होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। जब तक प्राधिकारी यह नहीं पाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, तब तक प्राधिकारी क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं करेंगे।
- xv. घरेलू उद्योग ने सकल अचल परिस्मृतियों पर अत्यधिक काल्पनिक प्रतिलाभ का दावा किया है। यह निवेदन किया जाता है कि नियोजित पूंजी के दोनों संघटकों पर समान रूप से 22% के प्रतिलाभ को अपना कर परिकलन करना बिल्कुल गलत है और उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस संबंध में एह्तियाती कार्रवाई करें तथा मौजूदा कर और व्यापक दर के ढांचे को ध्यान में रखते हुए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ का लागू करने की पद्धति में संशोधन करें।
- xvi. कम क्षमता उपयोग कृत्रिम रूप से घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत को बढ़ा रहा है। घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता का उचित सीमा तक उपयोग नहीं किया है। यह क्षमता उपयोग के ऐसे निम्न स्तर पर अपनी नियत ऊपरी लागत को वसूल करने के प्रयास कर रहा है, जो कि याचिकादाता को ऐसा करने से इसलिए रोक रही है क्योंकि घरेलू उद्योग असमान्य रूप से अधिक कीमतों को प्रभारित कर रहा है। इसके अतिरिक्त आरोपित कीमत कटौती होने के बावजूद भी याचिकादाता ने अपनी विक्रियां बढ़ाई हैं।
- xvii. केवल सकारात्मक कीमत कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन होने का तात्पर्य यह नहीं हो सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह स्पष्ट है कि याचिकादाता ने प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाया है, बल्कि वास्तव में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से संबंधित कोई भी प्राचल आयातों के कारण हुई गिरावट को नहीं दर्शाता है।
- xviii. बाजार में उचित व्यापन का प्रश्न वर्तमान मामले में अप्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान याचिका घरेलू उद्योग की अवस्थापना में आर्थिक मंदी का निर्धारण करने के रूप में नहीं है। यह एक नई जांच है और इसलिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वास्तविक और संभावित घिसाव पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जब तक कि याचिकादाता विभिन्न क्षति प्राचलों के संबंध में अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर इसको प्रमाणित नहीं कर देता है, तब तक यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि देश में उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप उसके कार्य-निष्पादन को क्षति पहुंची है।
- xix. आरोपित कीमत कटौतियों के बावजूद याचिकादाता अपनी विक्रियों और बाजार के हिस्से को बढ़ाने में समर्थ रहा है तथा साथ ही वह अपने घाटों को इतना अधिक कम करने में समर्थ हुआ है कि उसके निवेश पर प्रतिलाभ भी नकारात्मक की स्थिति से सकारात्मक बन गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपित कीमत कटौतियों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

37. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षति की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अन्य निवेदनों का निदान करता है। जांच के व्यौरे निम्नलिखित पैराओं में दिए गए हैं:

I. संचयी मूल्यांकन

38. वर्तमान मामले में प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है। संबद्ध देशों से निर्यात, पारस्पर रूप से और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा (3) के अनुसार पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन, पाटित आयातों और पाटित उत्पादों और घरेलू उत्पादों के बीच

प्रतिस्पर्धा की दशाओं के आलोक में उचित होगा। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित समझते हैं।

II. मात्रात्मक प्रभाव

(1) मांग का मूल्यांकन

39. संबद्ध वस्तुओं की मांग का निर्धारण, सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के साथ समान उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों के साथ जोड़ कर किया गया है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	संबद्ध देशों से कुल आयात	मी.टन	28,814	31,990	36,887	35,488
2	अन्य देशों से कुल आयात	मी.टन	400	495	370	256
3	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	305	2,182	3,239	6,533
4	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	-	-	-	-
5	कुल मांग	मी.टन	29,519	34,667	40,496	42,277

40. यह देखा गया है कि समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में सुसंगत वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में बहुविध वृद्धि हुई है।

(2) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और उनका हिस्सा

41. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

डीजीसीआईएंडएस के अनुसार

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	चीन जनवादी गणराज्य से आयात	मी.टन	11,878	12,712	10,237	8,810
2	जर्मनी से आयात	मी.टन	1,442	2,310	2,848	2,297
3	सऊदी अरब से आयात	मी.टन	15,495	16,968	23,802	24,381
4	संबद्ध देशों से कुल आयात	मी.टन	28,814	31,990	36,887	35,488
5	अन्य देश	मी.टन	400	495	370	256
6	कुल आयात		29,214	32,485	37,257	35,744
7	आयात की मात्रा में हिस्सा					
7 क	चीन जनवादी गणराज्य	%	40.66	39.13	27.48	24.65
7 ख	जर्मनी	%	4.93	7.11	7.64	6.43
7 ग	सऊदी अरब	%	53.04	52.23	63.89	68.21
7 घ	संबद्ध देशों का हिस्सा	%	98.63	98.48	99.01	99.28
7 ङ	अन्य देशों का हिस्सा	%	1.37	1.52	0.99	0.72
7 च	कुल	%	100	100	100	100

द्वितीयक स्रोत के आंकड़ों के अनुसार
(घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत)

क्रमांक	विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	चीन जनवादी गणराज्य	मी.टन	1,024	1,322	11,028	8,594
2	जर्मनी	मी.टन	471	701	2,019	2,281
3	सऊदी अरब	मी.टन	6,443	16,264	8,199	12,598
4	कुल संबद्ध देश	मी.टन	7,938	18,287	21,246	23,474
5	अन्य देश	मी.टन	26	124	255	261
6	कुल आयात	मी.टन	7,964	18,411	21,501	23,734
7	आयात की मात्रा में हिस्सा					
7 क	चीन जनवादी गणराज्य	%	12.86	7.18	51.29	36.21
7 ख	जर्मनी	%	5.91	3.81	9.39	9.61
7 ग	सऊदी अरब	%	80.90	88.34	38.13	53.08
7 घ	संबद्ध देशों का हिस्सा	%	99.67	99.33	98.81	98.90
7 ङ	अन्य देशों का हिस्सा	%	0.33	0.67	1.19	1.10
7 च	कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

42. यह देखा गया है कि -

- (क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात अत्यधिक हैं और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से उनमें वृद्धि हुई है।
- (ख) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े और डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आंकड़े दोनों आयातों में वृद्धि दर्शाते हैं, लेकिन डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़ों में दर्शाई गई प्रबल वृद्धि की तुलना में क्रमिक वृद्धि दर्शाते हैं।

III. कीमत के प्रभाव

43. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना है, जो कि सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा हो गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, के प्रसंग में की गई है।

(1) कीमत कटौती

44. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना, घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली के साथ की है।

क्रमांक	विवरण	पहुंच मूल्य	घरेलू उद्योग का एनएसआर	कीमत कटौती		
		रूपए/कि.ग्रा.		रूपए/कि.ग्रा.	%	सीमा
1	चीन जनवादी गणराज्य	56.66	***	***	***	1 -10
2	जर्मनी	54.75	***	***	***	5 - 15

क्रमांक	विवरण	पहुंच मूल्य	घरेलू उद्योग का एनएसआर	कीमत कटौती		
		रूपए/कि.ग्रा.	रूपए/कि.ग्रा.	रूपए/कि.ग्रा.	%	सीमा
3	सऊदी अरब	54.51	***	***	***	5 - 15
4	संबद्ध देश	55.06	***	***	***	5 - 15

45. यह देखा गया है कि चीन जनवादी गणराज्य, जर्मनी और सऊदी अरब के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है।

(2) कम कीमत पर बिक्री

46. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री करने से हुए नुकसान की भी जांच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई एनआईपी की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

क्रमांक	विवरण	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन		
		रूपए/कि.ग्रा.	रूपए/कि.ग्रा.	रूपए/कि.ग्रा.	%	सीमा
1	चीन जनवादी गणराज्य	***	56.66	***	***	10-20
2	जर्मनी	***	54.75	***	***	15-25
3	सऊदी अरब	***	54.51	***	***	15-25
4	संबद्ध देश	***	55.06	***	***	15-25

47. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से कम था।

(3) कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव, प्रभाव कीमतों का ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना है, जो कि सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	आयातों का पहुंच मूल्य	रूपए/कि.ग्रा.	61.58	52.31	50.68	55.06
1क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	82	89
2	बिक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	70	69
3	घरेलू बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
3क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	94	101

49. उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत बहुत अधिक थी, जिसमें सुसंगत रूप से गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग ने समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान अपनी बिक्री कीमत को उसी स्तर पर बनाए रखा है। इससे पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचल

50. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(1) बाजार का हिस्सा

51. घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	1.03	6.29	8.00	15.45
2	अन्य भारतीय उत्पादक	%	-	-	-	-
3	संबद्ध देशों से आयात	%	97.61	92.28	91.09	83.94
4	अन्य देशों से आयात	%	1.36	1.43	0.91	0.61
5	भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	97.61	92.28	91.09	83.94
6	घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
6 क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	37	23	12

52. यह देखा गया है कि समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि उसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों के आयातों के हिस्से में कमी हुई है। अन्य देशों से आयातों का हिस्सा नगण्य स्तर पर बना हुआ है।

53. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक होने के कारण बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाने में समर्थ रहा है और आयातों का हिस्सा कम हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग का हिस्सा लगभग 15.45% मात्र है और 84% भारतीय मांग की पूर्ति अभी भी संबद्ध देशों द्वारा की जाती है।

54. समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू खपत/मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है, हालांकि यह अभी भी अत्यधिक है।

(2) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

55. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था:-

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	स्थापित क्षमता	मी.टन	30,000	30,000	30,000	30,000
2	उत्पादन	मी.टन	701	2,095	3,901	7,035
3	क्षमता उपयोग	%	2.34	6.98	13.00	23.45
4	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	305	2,260	3,535	6,712

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
4 क	घरेलू बिक्रियां	मी.टन	305	2,182	3,239	6,533
4 ख	निर्यात बिक्रियां	मी.टन	-	***	***	***
4 ख (i)	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	375	227

56. यह देखा गया है कि समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है, लेकिन जांच अवधि के दौरान उनमें गिरावट आई है।

(3) लाभप्रदता

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	लाभ/(हानि)	लाख रूपए	(***)	(***)	(***)	***
1 क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(415)	(89)	313
2	लाभ/(हानि)	रूपए/कि.ग्रा.	(***)	(***)	(***)	***
2 क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(58)	(8)	15
3	आरओसीई	%	(***)	(***)	(***)	***
3 क	आरओसीई	सीमा %	(0-5)	(5-10)	(0-5)	5-10

57. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने लाभ को विशेष स्तर तक बढ़ा दिया है और यह जांच अवधि के दौरान सकारात्मक बन गया है। नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) में भी सुधार हुआ है और जांच अवधि के दौरान यह सकारात्मक बन गया है।

58. घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि जांच अवधि के दौरान अर्जित किया गया लाभ उचित स्तर पर नहीं है और यदि पाटित आयातों के कारण कोई कीमत कटौती/कीमत ह्रास नहीं होता, तो घरेलू उद्योग बेहतर लाभ अर्जित कर सकता था। नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के लिए घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह समग्र क्षति जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर पर्याप्त प्रतिलाभ नहीं अर्जित कर सका है, हालांकि जांच अवधि के दौरान इसकी स्थिति सकारात्मक थी।

(4) माल सूचियां

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17
औसत माल सूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	158	208	244

59. यह देखा गया है कि समग्र क्षति अवधि और जांच के दौरान घरेलू उद्योग के पास औसत माल सूची में वृद्धि हुई है, लेकिन औसत स्वीकार्य मालसूची के स्तरों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बड़ी हुई मालसूची के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

(5) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता

क्रमांक	विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
1 क	सूचीबद्ध	सूचक	100	117	117	350
2	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/ कर्मचारी	***	***	***	***
2 क	सूचीबद्ध	सूचक	100	256	477	287

60. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर ने भी वही प्रवृत्तियाँ दर्शाई हैं, जो कि उत्पादन की रही हैं तथा क्षति अवधि और जांच अवधि में इनमें वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त उत्पादकता प्रति कर्मचारी में भी सुधार हुआ है।

(6) पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

61. याचिकादाता ने यह निवेदन किया है कि देश में उत्पाद की मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्र और मशीनरी में अत्यधिक निवेश किया है और लगभग 42,000 मी.टन की मांग की तुलना में 30,000 मी.टन की क्षमता स्थापित की है। तथापि, इन निवेशों और मांग में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग द्वारा जांच अवधि के दौरान किया गया अत्यधिक क्षमता उपयोग लगभग 24% था। इस प्रकार इस चरण में और निवेश किए जाने का प्रश्न महत्व नहीं रखता है। तथापि, याचिकादाताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा इस समय प्राप्त किया गया नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ उचित नहीं है और किसी भी प्रकार का अन्य निवेश, पहले से किए गए निवेशों की सुस्थिरता पर निर्भर करेगा।

(7) पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन

62. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात देश में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन बहुत अधिक है।

(8) संवृद्धि

63. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना से यह देखा गया है कि क्षमता उपयोग, बिक्री कीमत, लाभ और आरओआई आदि के संबंध में संवृद्धि सकारात्मक थी।

(9) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

64. विषय देशों से आयात की कीमतों की जांच, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारक, दिखाते हैं कि विषय देशों से आयातित माल का पहुंच मूल्य क्षति रहित कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य से नीचे है, जिससे भारतीय बाजार में बिक्री के तहत सकारात्मक मूल्य कम है और कीमत कम है। हालांकि, पीयूसी की देश की मांग में मामूली हिस्से के बावजूद डी आई की नेट बिक्री मूल्यांकन लगातार विषय देशों से विषय वस्तु के पहुंच मूल्य से ऊपर रही है।

65. ऐसा देखा जाता है कि निरपेक्ष शर्तों में विषय देशों से डंप किए गए आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है, हालांकि भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में यह भी कमी आई है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में घरेलू उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई, पीओआई में डंप किए गए आयात का बाजार हिस्सा लगभग 84% रहा और घरेलू उद्योग केवल 24% क्षमता उपयोग पर ही काम कर रहा था। खराब अंडर-कटिंग और मूल्य के तहत कीमतों के मामले में डंप किए गए आयातों का कुछ प्रतिकूल मूल्य प्रभाव पड़ा है। हालांकि, डीआई की नेट बिक्री मूल्यांकन भूमिगत कीमतों से लगभग 8 से 11% बनी हुई है। नतीजतन, चोट अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त लाभ और आरओआई ने सुधार दिखाया है और पीओआई के दौरान सकारात्मक था।

V. क्षति मार्जिन की मात्रा

66. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति कीमत की तुलना संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी	एलवी	आईएम		
		अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	अमरीकी डालर/मी.टन	%	सीमा
1	शॉनडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	***	***	***	***	5-15
2	लूक्सी केमिकल ग्रुप कोर अल्कली केमिकल ब्रांच/ शॉनडोंग लियाचुंग लूक्सी न्यू मेटेरियल सेल कंपनी लिमिटेड/ लूक्सी केमिकल (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	***	***	***	***	15-25

3	मेथानोल केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब	***	***	***	***	15-25
4	जर्मनी	***	***	***	***	15-25

छ. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

67. पाठन रोधी नियमावली एवं करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक कारकों, इसकी कम कीमत पर बिक्री और कीमत पर दबाव एवं न्यूनीकरण के प्रभावों के मामले में, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की वास्तविक क्षति, मात्रा और कीमत के प्रभावों की मौजूदगी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह देखने के लिए कार्यवाही की कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान कर सकता था।

i तीसरे देश से आयात

68. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात मात्रा की मामले में बहुत अधिक नहीं है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती हो अथवा क्षति होने का कोई खतरा हो। जांच की अवधि के दौरान कुल आयातों का लगभग 99 प्रतिशत संबद्ध देशों से होता है।

ii मांग में संकुचन

69. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में स्वतंत्र रूप में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया है। तदनुसार मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती है। क्षति समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का हिस्सा एक जैसा रहा है।

iii विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें और उनके बीच प्रतियोगिता

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग प्रभावित हो सकता था।

iv प्रौद्योगिकी का विकास

71. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी के विकास का घरेलू उद्योग के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

v खपत के पैटर्न में परिवर्तन

72. घरेलू उद्योग उस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिसका आयात भारत में किया गया है। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन ऐसा कारक नहीं हो सकता है जिसके कारण घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ सकता था।

vi निर्यात निष्पादन

73. डीआई ने 2015-16 से वस्तुओं का निर्यात किया है, हालांकि, वर्तमान बिक्री के लिए घरेलू बिक्री की पहचान और जांच की गई है।

vii अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना पर विचार विश्लेषण के लिए किया गया है।

viii घरेलू उद्योग की उत्पादकता

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और उत्पादकता एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति के रूप में देखी गई है।

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

76. प्रकटन पश्चात निवेदनों का संक्षिप्त विवरण और उनका मिलान निम्नानुसार है :

घरेलू उद्योग के विचार

77. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :

- i. एक्सपोर्ट्स जीनियस के आंकड़ों के प्रयोग करने का निर्णय पूर्णतया याचिका दायर करने के समय डी जी सी आई एंड एस टी/टी के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण था और याचिकादाता ने कभी भी द्वितीयक स्रोत के आंकड़ों पर अथवा किसी भी अन्य तरीके से विश्वास करके प्राधिकारी के समक्ष आयात और क्षति की किसी भी बनावटी स्थिति को दर्शाने का कभी प्रयास नहीं किया है।
- ii. याचिकादाता ने द्वितीयक स्रोत के आंकड़े निर्णायक आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत नहीं किए थे केवल उसने उक्त आंकड़ों का उपयोग उस स्थिति में तथ्यों के साथ अत्यंत विश्वसनीय आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किए थे।
- iii. डी जी सी आई एंड एस टी/टी आंकड़ों के अनुसार आयातों का उच्चतर स्तर याचिकादाता द्वारा दी गई याचिका में क्षति के दावों को संदेहास्पद नहीं बनाता है। यहां तक कि प्रतिवादी निर्यातकों से पाटन मार्जिन भी बहुत अधिक है। इस प्रकार, याचिकादाता द्वारा पाटन के दावे प्रमाणित होते हैं।
- iv. यह विनम्र अनुरोध है कि शॉन्डोंग हुवालुल हेंगशेंग कैमिकल कंपनी लिमिटेड को कोई भी विशिष्ट मार्जिन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, यदि उन्होंने जांच अवधि के दौरान बहुत कम अथवा नगण्य वाणिज्यिक मात्रा में निर्यात किए हैं। शॉन्डोंग हुवालुल हेंगशेंग कैमिकल कंपनी लिमिटेड भारत में डीएमएफ की प्रमुख निर्यातक कंपनी नहीं थी। इस कंपनी के पास अत्यधिक निर्यात करने की क्षमता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्यातक कंपनी की कीमत पहले से ही कम होनी शुरू हो गई है।
- v. क्षति प्राचलों के तथ्यपरक प्रकटन से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है और हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह निष्कर्ष दें कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। हालांकि घरेलू उद्योग की बिक्रियां मांग में वृद्धि होने से बढ़ी हैं लेकिन पाटित आयातों की उपस्थिति बहुत उच्च स्तर पर है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की स्थिति से भी सामान्य कार्य निष्पादन से कम तथा आर्थिक क्षति की स्थिति का पता चला है।
- vi. सूचीकार्य प्रतिलाभ में कुछ परिकलन त्रुटि होने का पता चलता है। प्राधिकारी द्वारा परिकलित प्रतिलाभ सही नहीं है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

78. विभिन्न प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

- i. घरेलू उद्योग ने जांच शुरू किए जाने के समय वर्तमान जांच में सही और पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है जोकि वर्तमान जांच को समाप्त करने के लिए एक स्वतः पर्याप्त आधार है।
- ii. यह अनुरोध है कि चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उनके रिकॉर्ड के आधार पर किया जाए न कि संरचित सामान्य मूल्य के आधार पर। साथ ही यह भी अनुरोध है कि वर्तमान जांच में चीन के निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सऊदी अरब से प्राप्त सूचना पर विचार किया जाए।
- iii. कैमानोल का सामान्य मूल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क(1)(ग) में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार किया जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसी कोई घटना अथवा रिकॉर्ड किए गए किसी तथ्य का प्रकटन नहीं किया है जिसमें यह उल्लेख हो कि कैमानोल ने प्रश्नावली का अपूर्ण उत्तर अथवा अपर्याप्त सूचना प्रस्तुत की है जिससे धारा 9क(1)(ग)(ii)(क) और 9क(1)(ग)(ii)(ख) के अंतर्गत उल्लिखित संरचना की बाकी क्रियाविधियों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध उत्तम तथ्यों पर विश्वास करते हुए और घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत का प्रयोग करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली सांविधिक स्कीम का स्पष्ट अनादर है और यह अधारणीय है।
- iv. कैमानोल के खिलाफ लागू किए गए श्रेष्ठ तथ्यों का प्रकटन नहीं किया गया है जिससे कैमानोल को उस पर टिप्पणी देने के अवसर से वंचित किया गया है।
- v. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर विचारित सामान्य मूल्य उचित नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत केवल 23 प्रतिशत क्षमता उपयोग किए जाने के कारण बिक्रित है जिससे उसके उत्पादन की लागत बढ़ गई है।
- vi. लुक्सी समूह के निर्यातक के लिए जांच अवधि में मासिक और त्रैमासिक आधार पर निर्यात कीमतों में अत्यधिक अंतर व्याप्त है।

- vii. याचिकादाता की खपत के मानदंड अथवा जांच अवधि में परिवर्तन लागत संयंत्र के कम उपयोग के कारण असामान्य रूप से अधिक थी। इसका उपयोग ऐसे विदेशी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु नहीं किया जा सकता है जोकि संयंत्रों को क्षमता उपयोग के अधिक विभिन्न स्तर पर प्रचालित कर रहे हैं।
- viii. घरेलू उद्योग को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है क्योंकि सभी संबद्ध आर्थिक प्राचल अत्यधिक सुधार दर्शाते हैं। अनुबंध-2 के पैरा (iv) में निर्धारित आर्थिक प्राचलों के समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में पर्याप्त सुधार आया है और संबद्ध देशों से आयातों ने उसके कार्य निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह विचार है कि केवल पाटन मार्जिन की मौजूदगी घरेलू उद्योग की आर्थिक क्षति को प्रदर्शित करती है, तो उसके अकाट्य कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि केवल पाटन मार्जिन की मौजूदगी के कारण ही क्यों सकारात्मक निष्पादन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जोकि अन्य 14 प्राचलों में दिखाई दिया है।
- ix. घरेलू उद्योग ने आयातों में 196% की वृद्धि को दर्शाकर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से आयात के आंकड़ों के विशेष स्रोत का उपयोग किया है जबकि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार आयातों में वास्तविक वृद्धि आधार वर्ष की तुलना में 23% मात्र थी और उससे तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 की तुलना में जांच अवधि में आयातों में वस्तुतः 5% तक की कमी आई है।
- x. घरेलू उद्योग की बिक्रियां असामान्य रूप से आयातों में वृद्धि की तुलना में अधिक है। यदि आयात अभी भी अत्यधिक बने हुए हैं तो उसका कारण देश में मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर है।
- xi. समान वस्तु के घरेलू बाजार पर संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xii. जैसाकि माननीय सेस्टेट ने ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 211 (270) ई. एल. टी. 696 (ट्राई-डेल) के मामले में निर्धारित किया है, कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री होना क्षति के कारक नहीं हैं। जहां तक कि घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण करने का संबंध है, कम कीमत पर बिक्री होना एक अप्रासंगिक कारक है।
- xiii. कोई कारणात्मक संबंध प्रमाणित नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- xiv. उचित लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के लिए घरेलू उद्योग के निवेदनों का कोई महत्व नहीं है।
- xv. अन्य कारक घरेलू उद्योग पर प्रभाव डाल रहे हैं और उसे अनुकूलतम क्षमता उपयोग करने से रोक रहे हैं।
- xvi. घरेलू उद्योग बहु-उत्पाद कंपनी है और वह लाभ अर्जित कर रही है, इसलिए निधियां जुटाने की उसकी क्षमता, नई शुरू की गई संबद्ध वस्तुओं के कार्य निष्पादन द्वारा प्रभावित नहीं हुई है।
- xvii. याचिकादाता ने हाल ही में उत्पादन करना शुरू किया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया श्रेष्ठ उपयोग 23%, तक है इसलिए क्षमता उपयोग के इतने निचले स्तर पर एनआईपी का निर्धारण करना अत्यंत अनुचित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

79. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा प्रकटन पश्चात चरण पर उठाए गए मुद्दों की जांच उपरोक्त संबद्ध पैराओं में पहले ही कर दी गई है।

अ. निष्कर्ष

80. इस जांच परिणाम में यथा अभिलिखित प्राधिकारी के समक्ष हितवद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों और उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- i. सऊदी अरब से भारत में निर्यात किए गए पीयूसी की मात्रा पूरी जांच अवधि में लगातार और काफी बड़ी है, जबकि जर्मनी की मात्रा लगातार बड़ी नहीं है। पीओआई के दौरान चीन से निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है आयात की बड़ी मात्रा देश में बढ़ती मांग के जवाब में है और डीआई के प्रदर्शन में सकारात्मक वृद्धि के कारण डीआई को सीधे प्रभावित नहीं कर रही है।
- ii. घरेलू उद्योग के स्वास्थ्य में समग्र सुधार है। आधार वर्ष (2014-15) से बाद के वर्षों में उत्पादन कई गुना बढ़ गया है और पीओआई के दौरान आधार वर्ष के उत्पादन के 10 गुना तक पहुंच गया है। डीआई की बिक्री में भी कई गुना वृद्धि हुई है।
- iii. डीआई की स्पष्ट सकारात्मक वृद्धि इस तथ्य के बावजूद है कि इसी अवधि के दौरान, भारतीय खपत का 97% हिस्सा आयात में 83.9% की गिरावट आई है, हालांकि वे अभी भी पूर्ण शर्तों में पर्याप्त हैं।

- iv. आर्थिक मानकों का विश्लेषण इंगित करता है कि घरेलू उद्योग को चोट को कथित आयातित आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि कथित डंपिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग में भौतिक चोट लगती है।

ट. सिफारिशें

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद यह प्रमाणित हुआ है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है तथा उपरोक्त कारणों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्राधिकारी का यह विचार है कि वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य, सउदी अरब और जर्मनी से भारत को "डी-मिथइल फोर्मेमाइड (डीएमएफ)" के आयात के संबंध में कोई पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश नहीं की है।

82. इस परिणाम पर आधारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के मैसर्स जिन्दल पॉली फिल्म लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 8202/2017 पर लिए गए निर्णय के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2018

FINAL FINDING

(Case No. OI-42/2017)

Subject: Final Finding in the Anti-dumping investigation concerning imports of 'Di Methyl Formamide' (DMF) originating in or exported from China PR, Germany and Saudi Arabia.

1. **F.No. 6/37/2017-DGAD.**—M/s. Balaji Amines Ltd (hereinafter referred to as the "applicant" or "domestic industry") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of 'Di Methyl Formamide' (DMF) originating in or exported from China PR, Germany and Saudi Arabia (hereinafter also referred to as subject countries).

2. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No. 6/37/2017-DGAD dated 22.1.2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigations in accordance with the Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, Germany and Saudi Arabia (hereinafter also referred to as the subject countries) and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

- i. The Authority notified the Embassy of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- ii. The Authority issued a notification dated 22.1.2018, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
- iii. The Embassy of the subject countries in India was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within prescribed time limit.
- iv. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. Methanol Chemicals Company, Saudi Arabia
 2. Fahad Thnayan AI Thnayan and PA, Saudi Arabia
 3. Barwil Agencies Ltd, Saudi Arabia
 4. Rabochem AG, Germany
 5. Taminco BVBA, Germany
 6. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co Ltd, China PR
 7. Hualu Holding Group Co., Ltd China PR
 8. Zibo Luzhong Chemical & Light Industry Co., Ltd China PR
 9. Anhui Huaihua Fine Chemicals Co., Ltd China PR
 10. Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd China PR
- v. In response to the above notification, following exporters/ producers have submitted exporter questionnaire responses.
 1. Methanol Chemicals Company, Saudi Arabia,
 2. M/s Luxi Chemical Group Co., Ltd, China PR,
 3. M/s Shandong Liaocheng Luxi New Material Sale Co., Ltd., China PR,
 4. M/s Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co., Limited, Hong Kong,
 5. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.
- vi. A Supplementary questionnaire on Market Economy conditions was also sent to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with a request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit.
- vii. The producers/exporters who have responded from China PR filed only the EQ Responses and have not filed replies to the questionnaire to rebut the Non Market Economy presumption of China PR. In the absence of any substantiated claims for Market Economy Treatment (MET) in the prescribed format by the responding producer/exporters from China PR, none of the producers/exporters from China PR are given market economy treatment in the present investigation.
- viii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. M/s. Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd
 2. M/s. Symed Labs Ltd
 3. M/s. Matrix Laboratories Ltd
 4. M/s. Dorf-Ketal Chemicals India Pvt Ltd
 5. M/s. Harman Finochem Ltd
 6. M/s. Ramkamal Chemicals Pvt Ltd

7. M/s. Piramal Enterprises Ltd
 8. M/s. Matrix Laboratories Ltd
 9. M/s. AMI Organics Pvt Ltd
 10. M/s. Indian Acrylics Ltd
 11. M/s. Wockhardt Ltd
 12. M/s. Yogesh Dyestuff Products Pvt Ltd
 13. M/s. Sun Pharmaceutical Industries Ltd
 14. M/s. Lupin Ltd
 15. M/s. Aurobindo Pharma Ltd
- ix. The following importers/users have submitted importers questionnaire responses:
1. M/s Indian Accrylics Ltd.
 2. M/s Aurobindo Pharma Ltd
 3. M/s Pasupati Acrylon Ltd.
 4. M/s Ramkamal Chemicals Pvt Ltd
 5. M/s Ami Organics Pvt Ltd.
 6. M/s Laurus Lab Ltd.
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xi. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
- xiii. The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;
- xiv. The petition was filed on the basis of secondary source import data (Export Genius), the Authority had examined the same and found sufficient evidence for dumping and injury for initiation of investigation. The Export Genius was kept in the public file as a part of the petition. During the course of investigation, the Authority sought transaction by transaction import data for the injury period and POI from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The Authority has relied upon import data procured from DGCI&S for analysis of various parameters in the present investigation.
- xv. Investigation was carried out for the period starting from 1st October 2016 to 30th September 2017. The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16, Apr'16-Mar'17 and the Period of Investigation (POI).
- xvi. The Authority held oral hearing in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules on 4.5.2018, providing opportunity to the interested parties to present their views orally. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of their views expressed orally by 11.5.2018, followed by rejoinder submissions by 18.5.2018.

- xvii. The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been addressed in this Final Finding. The submissions filed by Embassy of subject countries/Associations/Federations/Foundations has been duly considered and addressed appropriately.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xix. A Disclosure Statement was issued to interested parties on 28.9.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 09.10.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xx. *** in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate for the present investigation is 1 US \$ = Rs 66.53.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Di Methyl Formamide (DMF)". It is a colorless, high boiling polar aprotic solvent with a characteristic odor. It is stable on heating and under its distillation temperature range and is freely miscible with water, alcohols, ethers, ketones, ester, carbon disulfide and chlorinated and aromatic hydrocarbons.
5. The uses of the subject goods can be broadly categorized as follows;
- As a solvent in pharmaceuticals manufacturing;
 - As a solvents in Acrylic Polymers manufacturing;
 - As a feedstock for synthesis of derivatives of DMF;
 - As a solvent in pesticides formulations.
6. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The PUC has a specific HS code 2921 1110 under Chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.
7. The Authority notes that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject countries. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that goods produced by the applicant domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries in accordance with the AD Rules.
8. None of the interested parties have put forward any issues regarding the PUC and the scope thereof.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

9. The domestic industry has submitted that M/s Balaji Amines Ltd is the sole producer of the subject goods in India and hence their production constitutes 100% share of total Indian production. M/s RCF Ltd was a producer of subject goods but has not produced the subject goods for some time now and M/s RCF Ltd has filed a letter of support for the present investigation. The position of RCF supports the argument of the petitioner that dumping can cause closure of DMF plant of M/s Balaji also, if no AD Duties are imposed on the subject goods at the earliest.
10. The exporter/importer has submitted that M/s Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited have supported the present investigation vide letter dated 31.5.2018 though they do not have any locus standing. The submission that RCF suffered due to dumped imports and unfair competition is of no relevance and it

cannot be considered because RCF has not produced the subject goods in the injury analysis period or the POI. Merely having production capacities for the like article would not satisfy the requirement of Domestic Industry. Petitioner holds no brief with regard to RCF. The statement has been made without any knowledge with regard to RCF operations and without any brief from RCF. The petitioner cannot guarantee that RCF will start production of DMF. All such claims must be completely rejected

11. The Authority examined the application filed by M/s Balaji Amines Ltd., who is presently the only producer of subject goods in India. The other producers namely M/s Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd. have closed their production. M/s Balaji Amines Ltd. have not imported the PUC from the subject countries and are not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.

12. It is also noted that there have not been any submission disputing the claim of petitioner as eligible domestic industry. However, the Authority has taken note of the support to the present investigation extended by RCF Ltd after initiation of the present investigation which does not require any examination as the company did not produce the subject goods during the POI and has no locus standi to be identified as DI.

13. The Authority determined that the petitioner, who presently holds 100% share of total domestic production, constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

14. The petitioner has stated that they have claimed confidentiality on certain information and have disclosed the volume parameters to allow the opposing parties to understand the case better, however, the exporters/importers in the present case have not disclosed even the volume information and to hide such excessive claims of confidentiality, an allegation of excessive confidentiality is raised against the applicant which is not true. The opposing parties should at least give a range of their actual volume of export/import so that the petitioner also would be able to provide its comments on the submissions by the opposing parties.

15. The producers/exporters/importers/other interested parties have submitted that the domestic industry has kept lots of information as confidential without providing any legitimate reasons and in the absence of such information, the exporter has been denied of a reasonable opportunity to make submissions to defend their interest by making their effective comments. The non-confidential version of the Petition does not allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein. The Petitioner is required to show justification for its claim but has failed to do so in response to the Calculations of working capital, Interest on Term Loans, Depreciation, Details of misc. income earned during the year, Details of WIP at the beginning and end of the investigation period. In a multi business company like Balaji Amines Limited, the Annual reports are consolidated for various products in each segment and it is not possible to assess such consolidated financial information and link the same to the product under consideration. The transaction wise import data has also not been furnished in excel format.

16. The Authority examined the submissions. It is noted that non confidential version of the information provided by various interested parties to others was made available through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6 (7).

17. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the justification of their claims and the specific provisions of law as interpreted by the Hon'ble Supreme Court. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

18. With regard to the contentions on the transaction-wise and sorted import data, it is noted that the Authority has relied upon transaction wise import data procured from DGCI&S for the purpose of present investigation. Any of the interested parties could seek data from the Authority in terms of trade notice no. 07/2018 dated 15th March, 2018.

E. MISCELLANEOUS ISSUES**Submissions of the Domestic Industry**

19. The submissions made by the domestic industry pertaining to miscellaneous issues are as follows:
- i. The contention of certain parties that the petition does not meet the evidentiary and legal standards is not of any merit. Best possible efforts were made by the petitioner to adduce reliable and adequate evidences to substantiate various claims in the petition. Even the estimates on adjustments from Export Price were carried out as per the best available information basis and such methodologies are permissible under the law and the basis of every information relied upon is provided in the petition also. The Authority may note that the petitioner has acted to best of its ability to adduce correct evidences in the petition and the claims otherwise are bereft of any merit.
 - ii. It has been contended that there is ADD on various products produced by Balaji. The statement is wrong. There is ADD on DMAC currently in force and DMAC is produced by Balaji and RCF Ltd. Duties were earlier imposed on a product called Morpholine produced by Balaji which was subjected to MTR first and then discontinued/no SSR was initiated. The company is doing well on certain products which do not negate injury in DMF.
 - iii. It has been contended that the DI did not take cognizance of summary import data published by DGCI&S and omission of the said data is a huge mistake and was done to show a huge jump in import by relying on some other source data. The contention has no basis and the mistake is accused on a set of data which is not used by the DI for a valid reason. The DGCI&S summary data was not available for the complete POI when the petition was filed and there was no logic in using the same for certain years except POI. The DI then called in T/T data as per secondary source to ensure correct import data for the entire POI. It was noted in the T/T data that imports of PUC were made under various subheadings other than the dedicated classification and it was also noted that imports of certain other products were also made under the dedicated classification for DMF ruling out the reliability on DGCI&S summary data completely. It was incumbent upon the DI to use the most reliable data to present its case. It is reiterated that DGCI&S summary data has impurities in it which makes the said data not reliable in the present case. Thus, the allegation of the opposing party is not of any merit and done only to insinuate wrong doings by the DI which has no merit.
 - iv. The facts of the present case show a clear case of material injury. The company started its production a few years back but could only reach to a miniscule level of performance on various parameters by the present period under investigation.

Submissions of the opposing interested parties

20. The submissions of various interested parties are summarized as follows:
- i. The petitioner has not brought about any substantive evidence to prove the condition for initiation of the Anti-Dumping Investigation, while the investigating authority has not carried out appropriate, enough scrutiny to the related facts. The petition does not meet the evidentiary and legal standards regarding dumping, injury and a causal relation between the alleged dumping and injury.
 - ii. The volume of import reported by petitioner in the petition are grossly low as compared to volume of imports reported under dedicated classification itself as per DGCI&S, leave aside imports reported in other classifications. This clearly speaks very adversely on the accuracy of the information contained in the petition. The kind of difference between the volume of imports reported in the petition and volume of imports reported under the dedicated classification itself is so alarmingly different that the same casts serious doubts about the accuracy of the information. The sufficiency of evidence for the purpose of initiation as set in *Guatemala — Cement II* case by WTO is not met in the present case.
 - iii. There is ADD on various products produced by the petitioner namely M/s Balaji Amines Ltd indicating a tendency to seek overprotection in the garb of trade remedy measures.

Examination by the Authority

21. The miscellaneous submissions have been examined as under:

- i. As regards the allegation regarding the initiation, the Authority notes that the initiation was done on the basis of prima facie evidences/facts provided by the Domestic Industry on various claims made by it in the application.
- ii. It is the established practice that quality of information and evidence improves subsequently during the course of the investigation.
- iii. As regards the submission that the domestic industry did not take cognizance of summary import data published by DGCI&S at the time of petition, it is noted that the petitioner had relied upon import data reported in a secondary source namely Export Genius. Petitioner had claimed that secondary source data was used for the reason that the PUC in spite of having a dedicated customs classification code at eight digit level is still being imported under various other subheadings. At that point in time it was considered sufficient by the Authority to initiate investigation.
- iv. During the course of investigation, the Authority has obtained DGCI&S transaction wise data for the POI and previous three years. The T/T import data from DGCI&S has been used in the present case for determination of import volume and value into the country. It is noted that the difference in secondary source data relied upon by the petitioner and the DGCI&S data is huge for the entire injury period and POI. This kind of difference in the volume of imports reported in the petition and volume of imports reported in the DGCI&S which is alarmingly different definitely casts a serious doubts about the accuracy of the information furnished by the petitioner and the trends of injury claimed by the petitioner.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

Views of the Domestic industry

22. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. China PR should be treated as nonmarket economy country as the responding producers/exporters from China PR have not rebutted the presumption of NME by replying to the relevant Supplementary questionnaire format. The Normal Value for Chinese producers should be determined based on Para 7 of Annexure I to the AD Rules.
- ii. Constructed Normal Value based on cost of production of petitioner adjusted for reasonable profit shall be the appropriate methodology and the Authority is requested to adopt the said approach in the present case also. Such best available information shall be applicable for Germany also since there is no cooperation from producers/exporters from Germany.
- iii. The import data relied upon in the petition was based on secondary source information. A copy of such submission was made available in the public file also. It can be seen from data that the dumping margin from subject countries is significant and causing material injury to the domestic industry.
- iv. The product under consideration has been exported to India from subject countries below their normal values resulting in dumping;
- v. Methanol Chemical Company from Saudi Arabia has filed the EQ Response in the present matter. It can be noted from the EQ Response of the said party that the company is in losses and DMF constitutes a significant portion of its exports and also overall revenue. The DI clearly faces serious further threat from this large exporter apart from the injury already caused by its exports. It has been submitted in the EQ Response of the said exporter that they have a Gas supply agreement with some party and the name or the details of the agreement is not disclosed to the petitioner. It is requested that the Authority may subject the cost of production of the exporter to strict scrutiny as per Annexure I Para 1 to the Rules to see whether the cost of the exporter for the PUC reflect the cost associated with the production and sale of the PUC.
- vi. Certain parties have questioned the basis or normal value claimed by the petitioner and contended that the Authority should consider information from Saudi Arabia for the determination of normal value for the Chinese exporters in the current investigation. The claims are not on merit factually and legally. The exporters from China PR had the opportunity to rebut the NME presumption which they did not do. Hence, what is relevant for normal value in case of China PR is Para 7 of Annexure I. The Authority has

consistently followed the CNV method for China PR and the same principles should be followed in the present case also. Also, there is no comparison between economic conditions in China PR and Saudi and there is no legal or factual basis to consider Saudi as an appropriate surrogate country for China PR.

- vii. There are submissions made by the opposing parties that capacity utilization of DI should be adjusted to avoid effects of high cost for the purpose of CNV. The low capacity utilization was due to dumped imports and cost of DI as per actual details alone should be considered for CNV and other purposes. The exporters who materially injured the DI by adopting the practice of dumping cannot now argue that some unrealistically low CNV should be worked out so that exporters will be exonerated.

Views of the opposing interested parties

23. The following submissions have been made with regard to normal value, export price and dumping margin :—

- i. Consideration of producers from China P.R as non-market economy is inconsistent with legal provisions, hence, the normal value determination for China PR is arbitrary further resulting in a flawed dumping margin determination. The normal value for the companies from China PR in the current investigation is to be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods. Any other methodology used for the determination of normal value for Chinese exporters would be in violation of the obligations of India under the WTO.
- ii. The normal value for Chinese producers is constructed in the application by the DI based on the cost of production in India and considering the rate of profit at 5%. However, the item-wise cost details of the constructed normal value have not been provided.
- iii. Petitioner has not proved existence of any of the conditions necessitating the construction of normal value. The relevant provisions do not mention "non-availability" of data relating to domestic selling prices as a ground for construction of normal value.
- iv. For the subject countries which are market economy countries, the normal value must be based solely on Explanation (c) to Section 9A (1). The said explanation does not allow construction of normal value based on Domestic Industry's own costs.
- v. In the initiation notice, the DA has not explained whether such 'prima-facie' issues and inconsistencies were examined or not. While it is true that the final duty is imposed based on verified figures provided by the Respondents, such an approach renders the legal provisions relating to evidentiary thresholds for initiations redundant.
- vi. The NCV of the application does not contain any evidence with regard to the deductions claimed in Net Export Price. Further, inland freight and port handling charges have no relationship to the price of the product. Therefore, the very basis of calculating these expenses as a percentage of CIF or FOB price is incorrect. The data presented in the petition with regard to every adjustment are bare assertions unsubstantiated by evidence, which could not have been relied on for initiating the case.
- vii. Petitioner has not been able to adduce even single credible evidence regarding the prices prevailing in the domestic market of the exporting country, projecting equal normal values in all subject countries and unsubstantiated deductions towards allowances from export price.
- viii. The Normal Value considered on the basis of cost of production of the Domestic industry is not accurate as the domestic industry's cost of production is distorted. Additionally the sourcing of raw material is also a problem for the domestic industry, as they are relying on imports of raw material for production of the PUC, hence inflating the cost of production even more. The Constructed Normal Value cannot be adopted based on petitioner's data, as they have not utilized the production capacities to a very significant extent. The conversion costs of the petitioner is naturally very high and unreliable to represent reasonable costs for determination of normal value. Such being the case, the Constructed Normal Value cannot be determined based on such low capacity utilization.
- ix. The normal value has been calculated on the basis of cost of production of the Domestic Industry, which itself is inflated. The export price figures are based on secondary source data, which is not accurate. Hence, the dumping margin, as calculated by the DI is distorted and not reliable.
- x. The domestic industry has achieved capacity utilization which is much below the level of utilization

that can be achieved by such a plant. It is requested to consider the project report of the petitioner and optimum capacity utilization achieved therein. The CNV for China should be determined by considering optimum plant utilization levels as projected in the project feasibility report.

- xi. Petitioner has stated that they made efforts to obtain the information with regard to the domestic prices of the subject goods in the subject countries, but no price details were available in the public domain (with the exception of China PR which was treated as Non-Market Economy).
- xii. Petitioner has not proved existence for necessitating the construction of normal value. The relevant provisions do not mention “non-availability” of data relating to domestic selling prices as a ground for construction of normal value.
- xiii. It is requested that the Authority consider the information from Saudi Arabia for the determination of normal value for the Chinese exporters in the current investigation. The per unit fixed cost for the PUC are higher by about 3-4 times of the actual fixed cost. Thus it is requested that construction of the normal value on such basis is fundamentally flawed and is artificially inflated with a view to make out a case of dumping against exporters from Chinese whereas in reality it does not exist.
- xiv. In terms of the provisions of Para 7 it is submitted that the DI is under an obligation to inform, without unreasonable delay, the selection of market economy third country so as to give the parties concerned an opportunity to respond to the same.
- xv. For all the subject countries involved in the present investigation, except for China, the normal value has been ‘constructed’ in the application based on Domestic Industry’s own prices & costs. Such an approach of DI does not even ‘prima facie’ meet the conditions for determining normal value in terms of explanation (c) to Section 9A (1). For the subject countries which are market economy countries, the normal value must be based solely on Explanation (c) to Section 9A (1). The said explanation does not allow construction of normal value based on Domestic Industry’s own costs. BAL cannot devise their own methodology to determine normal value.

Examination by the Authority

24. The following interested parties from China PR and Saudi Arabia have filed responses and submissions with regard to Normal Value and export price. However, none of the parties from China PR have filed response in supplementary Questionnaire nor claimed market economy treatment. Also no response has been file from any of the exporters from Germany.

- i. M/s Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd.(Producer/Exporter)
- ii. M/s Luxi Chemical Group Co. Ltd. Chlor –Alkali Chemical Branch, China (Producer) along with and its exporter and trader M/s Shandong Liaocheng Luxi New Material Sale Co. Ltd. & M/s Luxi Chemical (HongKong) Co. Ltd
- iii. M/s Methanol Chemical Company (Producer/Exporter), Saudi Arabia

25. The submissions of various interested parties are summarized as follows:

I. CHINA PR

i. NORMAL VALUE

26. At the stage of initiation, the petitioners proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of the questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. The Chinese exporters filed questionnaire responses; however, none of them filed Market Economy Treatment questionnaires.

27. The Authority notes that the known Chinese producers/ exporters and the Government of China have been adequately notified about the requirement of submission of information in the form and manner prescribed and adequate opportunity was also granted to them to make their submissions in this regard. None of the producers have filed MET questionnaire, hence the Authority considers it appropriate to treat China PR

as a non-market economy country in the present investigation and proceeds with Para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

28. In view of the above, Normal value for the subject goods imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for raw materials and utilities, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry including thereupon reasonable profits.

ii. EXPORT PRICE

a. M/s Luxi Chemical Group Co., Ltd Chlor-Alkali Chemical Branch (Producer), M/s Liao Cheng Luxi New Material Sale Co. Ltd (Exporter) And M/s Luxi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd (Exporter)

29. From the exporters questionnaire response, it is noted that the producer M/s Luxi Chemical Group Co., Ltd has exported the subject goods to India during the POI through its related trader M/s Liao Cheng Luxi New Material Sale Co. Ltd and M/s Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co., Limited. Adjustment on account of inland freight, port charges and bank charges have been claimed and the same have been allowed by the Authority for computation of the export price at ex-factory. The net export price determined for exports to India is as shown in the Dumping Margin Table below.

b. M/s Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.

30. M/s Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. has filed exporters questionnaire response, it is noted that Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd., is a producer as well as exporter of the subject goods. During the POI, M/s Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd., exported subject goods to India directly. Adjustment on account of inland freight, port charges and bank charges have been claimed by the producer/exporter and the same have been allowed. Accordingly, the export price has been worked out for M/s Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd at ex-factory. The net export price determined for exports to India is as shown in the Dumping Margin Table below.

II. GERMANY

31. The Authority notes that no producer/ exporter from Germany have responded to the exporter's questionnaire in the present investigation. Therefore, the normal value has been determined on the basis of best facts available on record which is provided in the Dumping Margin Table herein below.

S.No.	Producer/ Exporter	CNV	NEP	DM		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co.Ltd. (producer/exporter), China PR	***	***	***	***	20-30
2	Luxi Chemical Group Chor alkali chemical branch (producer)/Shandong liaocheng Luxi new material sale co. Ltd/Luxi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd. China PR	***	***	***	***	35-45
3	Methanol Chemicals Company. Saudi Arabia	***	***	***	***	25-35
4	Germany	***	***	***	***	35-45

III. SAUDI ARABIA

a. M/s Methanol Chemicals Company

i. NORMAL VALUE

32. M/s Methanol Chemicals Company filed response to the questionnaire. The same has been examined and found that domestic sales of the subject goods are less than 5% of the total sales of the producer exporter and hence they do not satisfy the sufficiency test. In view thereof the Authority constructed the normal value on the basis of best facts available.

ii. EXPORT PRICE

33. M/s Methanol Chemicals Company has filed exporters questionnaire response, it is noted that they are a producer as well as exporter of the subject goods. During the POI, M/s Methanol Chemicals Company, exported subject goods to India directly. The sales to Indian customers are on FOB basis. Adjustment on account of inland freight, port charges and bank charges have been claimed and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, the export price has been worked out for Methanol Chemicals at ex-factory. The net export price and dumping margin determined for exports to India is as shown in the Dumping Margin Table below.

iv. DUMPING MARGIN

34. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing normal value and net export price at ex-factory level for the subject goods as below.

G. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**Views of the Domestic Industry**

35. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. Significant dumping in the imports of subject goods from subject countries. Such dumped imports increased over the years significantly. Imports from subject countries have been above the 3% threshold individually with highest imports from Saudi Arabia. The volume of dumped imports has increased significantly and has been holding about 84% of the market share in demand which prevented any notable penetration by DI into the domestic market. Resultantly, the DI ended up getting only about 15% share in the domestic demand during the POI and rest all been held by dumped imports. Third country imports were negligible.
- ii. The dumped prices of such imports were also at positive undercutting levels. Such price undercutting had multiple effects on the price parameters of injury which is further reflected in the below par situation in terms of profits, ROI etc.
- iii. The price increases prevented by significant level of price undercutting had a cascading effect on the profitability and ROI and the profitability in real terms remained negligible at very low level and ROI also have been at low single digit level showing the enormity of material injury suffered by the DI on account of dumping.
- iv. The volume levels of domestic industry remained at subdued or very negligible levels which are reflected in terms of very small production volume, below par capacity utilization and low sales volume and such below par volume position is when demand increased significantly and is clearly the effect of dumped imports.
- v. The severity of the dumping and consequent material injury is visible in subdued performance in both volume and value parameters. The DI has suffered material injury as envisaged in the Rule on account of dumping from subject countries.
- vi. It is highly unrealistic to say that the increase in sales from the base year to the POI when the demand during the POI was about 42277 MT is a reasonable growth. The actual volume in the POI itself is relevant and the exporters engaged in dumping cannot take the benefit of a low base year sales by the DI to cite increase in market share in terms of percentages to say that performance improved on a trend line.
- vii. Share of imports in relation to production may show a decline but the same is due to the low volume of production in the base year and do not show that there was no significant growth in the level of dumped imports including the POI.
- viii. The DI was clearly side lined from taking any benefit of domestic demand to some reasonable level leading to low production and sales which shows clear volume injury on account of such dumped imports.

- ix. The average prices of imports from subject countries have significantly declined by the POI over the base year. Price reductions were carried out by the exporters to maintain the volume of dumped imports and to keep the domestic industry away from supplying more in the domestic market. The DI could have increased the prices to a more significant level so as to achieve reasonable profits but the same was prevented by the dumped imports which were available at significantly undercutting levels. Price injury is visible in the present case.
- x. Price suppression/prevention of price increase to significant levels is visible in the fact that the NSR almost remained the same and the cost declined. Scope for price increases created by reduction in cost was adversely affected by dumped imports.
- xi. The installed capacity at the end of the domestic industry remained the same during the entire injury period and is sufficiently capable to meet significant part of the Indian demand.
- xii. The capacity utilization during the POI is clearly below par level and is the direct result of significant level of dumped imports from subject countries. The DI took at least 5 years and what has hampered better utilization of capacity is the presence of dumped imports all this while.
- xiii. Dumping is what prevented the DI from producing and selling more. Export sales of the DI in this period have shown some increase though the same was of very low level. Material injury on this factor is, thus, visible in such low production volume itself during the POI wherein the demand was very robust. ADD will help the DI to increase the production to countable levels.
- xiv. Dumped imports at significantly positive undercutting levels are the cause for low sales volume which signifies severe position of material injury.
- xv. The inventories with the DI were very significant during the POI. Such significant level of inventory was when the demand for the product registered superb growth in the country. The level of inventory clearly shows the pressure of dumped imports on the subject good produced by the domestic industry.
- xvi. The profits and ROI achieved by the DI during the POI do not show the one which it could achieve in the absence of dumping. The actual profits and ROI achieved by the DI during the POI was insignificant and much lower than what it could have achieved in the absence of dumping.
- xvii. The level of employment shows similar trend as that of production and the industry has the potential to create more employment should it be in a position to produce more and sell more. Productivity was at good levels during the POI that any underperformance in productivity was not the cause of injury. The element of wages in cost also showed similar trend of overall cost and any increase in wages per se was not the cause of injury.
- xviii. Material injury is reflected in subdued growth of the industry even after several years of being in production albeit low levels.
- xix. The DI also provided information relevant for the determination of Non Injurious Price and it would be seen that the landed value of imports were clearly at a price lower than the NIP leading to positive price underselling in the present case.
- xx. The non attribution analysis as presented in the petition shows clear causal link between dumping from subject countries and injury suffered by the DI on account of the same. Dumping prevented better performance by the DI and that establishes the causal link between dumping and material injury caused in the present case.
- xxi. Even a decline in all parameters may not show material injury as defined in the AD Agreement and determination of material injury has to be a more subjective analysis rather than a mere trend analysis. Analysis needs to be done in the present case by giving emphasis to the factual position of various parameters during the POI itself which would show the below par performance of the DI on various counts establishing material injury. Not achieving a prudent level of performance in the POI on a given parameter also shows material injury even though the same may have increased by the POI on a trend trajectory. This position is applicable to all most every parameter of injury in the present case.

- xxii. The material injury in the present case is visible in the fact that the injury parameters, both volume and price, remained at subdued and below par level during the POI as a result of dumping and the domestic industry cannot sustain for any longer under such circumstances without AD duties to remove such injurious effect of dumping. Subdued performance during the POI itself on account of dumping is the indicator of material injury during the POI in the present case and such below par performance is apparent in both volume and price parameters. Thus, the domestic industry has suffered material injury and contentions to the contrary are bereft of any merit.
- xxiii. The profitability achieved by the DI in the POI is far below than what it could have achieved in the absence of dumping and also far below than the 22% ROI which is considered by the Authority as a reasonable level of return for the purpose of non injurious price. The DI in the present case could reach only to a lower single digit ROI in the POI from a negative situation in the base year and such subdued performance in the POI signifies situation of material injury. The improvement over base year is negated by the below par level performance in the POI and performance in the POI signifies a situation of material injury.
- xxiv. It is submitted that the installed capacity of DMF with the DI 30000MT and is sufficient to meet about 75% of the Indian demand. But it is able to only sell less than 15% as a result of dumped imports in the market.

Views of the opposing interested parties

36. The following are the injury related submissions made by the opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. No material injury suffered by Domestic Industry as all relevant economic parameters show significant improvement.
- ii. There is no volume and price injury to the DI. The DI has not established the causal link between alleged dumped imports and alleged material injury to the domestic industry. For the causal link to be established between dumping and injury, the conditions of both para (ii) and para (iv) of Annexure II need to be met. In the present case, neither the conditions set forth in para (ii), nor the conditions prescribed in para (iv) are met. A bare perusal of the evidence of injury provided by the Domestic Industry in its petition clearly reveals none.
- iii. The imports from the targeted countries have at no point in time during the period considered put any sort of volume pressure on the sales of the Petitioner. Imports from the subject countries increased in absolute terms, the same reduced drastically when compared to the production of the Domestic Industry and consumption in the domestic market. Which clearly indicates that there is no volume effect of the imports from the subject countries.
- iv. Despite having positive price undercutting, Domestic Industry has improved its performance. Hence, price undercutting has no relevance in the present case. The imports from the subject countries have had no effect on the prices of the domestic prices of the subject goods.
- v. With the decrease in cost of sales globally, the landed value has also declined accordingly. However, selling price of the Domestic Industry has kept on increasing. Therefore, there is no correlation between the landed value and domestic selling price.
- vi. The petitioning company has understated the demand figures. The petitioner has in fact stated that the imports are occurring in other customs classifications as well, which implies that the actual demand may even be higher than this. This clearly shows that the petition is based on grossly inaccurate data and suffers from accuracy and adequacy of the data.
- vii. Sales, production, capacity utilization has significantly increased from base year to POI. There is a decline in inventories when viewed as a percentage of production and sales of the DI as the increase in inventories is not commensurate to the increase in production and sales; the cash profit has increased as a result, there is no adverse impact on cash flow; profits before tax and overall profits have also improved consistently throughout the injury analysis period; the employment generated by the Domestic Industry also increased manifold as the number of employees increased. wages paid, productivity per employee and productivity per day has increased. From a negative return on

investment during the base year, the same turned positive by the POI and the increase was a significant. It can also be seen that there has been consistent growth of the Domestic Industry on a year on year basis. On an examination of factors affecting domestic prices, while cost of sales has gone down, the selling price of the like article produced by the Domestic Industry has gone up. Therefore, imports from the subject countries are not affecting the domestic prices of the subject goods.

- viii. The overall analysis of the 15 economic parameters set out in para (iv) of Annexure II clearly reveal that the economic parameters of DI have improved tremendously and that imports from the subject countries have had no impact of the performance of the Domestic Industry as not a single relevant economic factor shows a negative trend as required by para (iv). Throughout the injury period the Domestic Industry has been consistently earning profits and the highest profits earned is during the period of investigation. If the petitioner is already earning 22% return on capital where is the case of injury.
- ix. Injury to the DI is caused due to other factors thus eliminating the chance of any causal link between dumped imports and injury to the Domestic Industry. The DI has exaggerated the increased import of the subject product, and deliberately invented injury to the DI.
- x. The capacity installed by the petitioner is not clear. The petitioner has a capacity of 18000MT to produce the product under consideration but has claimed a capacity of 30,000 MT in its petition. This is very low as compared to the existing demand of 42,473 MT. The petitioner is not producing enough quantity to fulfill the demand of the Domestic Industry. Products are being imported into India from subject countries to meet the demand of the downstream Indian industry. Subject goods are imported only to fill such demand and supply gap and not to cause injury to the Domestic Industry.
- xi. Although the volume of imports from Saudi Arabia increased, the market share has drastically reduced. Lower market share means lesser sales with more effort to sell the product. Increase in imports per se is not a factor showing consequent impact of dumping on the domestic industry.
- xii. Financial statement of DI discloses a healthy profit earned by the company during POR disputing their own claim of suffering loss.
- xiii. DI is also exporting the subject goods, however, such information is claimed as confidential.
- xiv. Price underselling in itself cannot be considered as a parameter showing injury to the DI. The question of injury margin and price underselling arise only when authority comes to a conclusion that the DI has suffered injury. Unless the Authority finds that the DI has suffered injury, the authority shall not determine injury margin.
- xv. The DI has claimed a highly inflated return on gross fixed assets. It is submitted that calculation of return by adopting 22% uniformly on both the components of capital employed is totally incorrect and needs to be reviewed. Authority is hereby requested to take the precautionary actions in this regard and modify the practice of applying 22% ROCE keeping in view existing tax and interest rate structure.
- xvi. The low capacity utilization is artificially inflating the Non-injurious Price of the DI. The DI has not even utilized its production capacity to a reasonable extent, it is trying to recover its fixed overhead cost at such low level of capacity utilization which is clearly preventing the petitioner from doing so, considering that the DI is charging abnormally high prices. Further, despite the alleged price undercutting, the petitioner has increased its sales.
- xvii. Only positive undercutting, dumping margin and injury margin cannot mean injury to the domestic industry. It is evident that the petitioner has shown nothing with regard to adverse effects, because indeed none of the parameters relating to the domestic industry performance shows deterioration because of imports.
- xviii. The question of reasonable penetration in the market is irrelevant to the present case as the present petition is not in the form of determination of material retardation to establishment of domestic industry. It is a fresh investigation and therefore authority is required to consider actual and potential deterioration in performance of the DI, which is clearly missing in the present case. unless the petitioner establishes deterioration on the basis of its performance in respect of various injury

parameters, it cannot establish that its performance has suffered as a result of dumping of the product in country.

- xix. Despite alleged price reductions, the petitioner was able to increase its sales, market share and consequently production & capacity utilization on one hand; and, it was able to reduce its losses so significantly that the return on investment even became positive from a situation of negative. It cannot therefore be said the alleged price reductions have led to deterioration in performance of the DI.

Examination by the Authority

37. The Authority has taken note of the submissions made by all the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Antidumping Rules. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various other submissions made by the interested parties. The details of the examination are mentioned in the following paragraphs:

I. CUMULATIVE ASSESSMENT

38. In the present case, the margin of dumping from each of the subject countries have been found to be more than the de minimis limit prescribed; the volume of dumped imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and the exports from the subject countries directly compete inter se and with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. In terms of Annexure II (iii) of the AD Rules, the Cumulative assessment of the effects of the dumped imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product. The Authority, therefore, considers it appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports from the subject countries.

II. VOLUME EFFECT

i. ASSESSMENT OF DEMAND

39. The demand of subject goods has been determined by adding the domestic sales of Indian producers of like product with the imports of the subject goods from all the countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S.

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Total Imports from Subject Countries	MT	28,814	31,990	36,887	35,488
2	Total Imports from Other Countries	MT	400	495	370	256
3	Sales of Domestic Industry	MT	305	2,182	3,239	6,533
4	Sales of Other Producers	MT	-	-	-	-
5	Total Demand	MT	29,519	34,667	40,496	42,277

40. It is seen that the demand of subject goods has consistently increased over the entire injury period and POI. It is also noted that the sale of domestic industry has increased multifold during the POI as compared to base year.

ii. IMPORT VOLUMES AND SHARE OF SUBJECT COUNTRIES

41. The volume of imports of the subject good from the subject countries has been analyzed as under:

As per DGCI&S

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Imports from China PR	MT	11,878	12,712	10,237	8,810
2	Imports from Germany	MT	1,442	2,310	2,848	2,297
3	Imports from Saudi Arabia	MT	15,495	16,968	23,802	24,381

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
4	Total Imports from Subject Countries	MT	28,814	31,990	36,887	35,488
5	Other Countries	MT	400	495	370	256
6	Total imports		29,214	32,485	37,257	35,744
7	Share in Import Volume					
7a	China PR	%	40.66	39.13	27.48	24.65
7b	Germany	%	4.93	7.11	7.64	6.43
7c	Saudi Arabia	%	53.04	52.23	63.89	68.21
7d	Share of Subject Countries	%	98.63	98.48	99.01	99.28
7e	Share of Other Countries	%	1.37	1.52	0.99	0.72
7f	Total	%	100	100	100	100

As per Secondary Source data (furnished by DI)

S.N.	Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	China PR	MT	1,024	1,322	11,028	8,594
2	Germany	MT	471	701	2,019	2,281
3	Saudi Arabia	MT	6,443	16,264	8,199	12,598
4	Total Subject Countries	MT	7,938	18,287	21,246	23,474
5	Other Country	MT	26	124	255	261
6	Total Imports	MT	7,964	18,411	21,501	23,734
7	Share in Import Volume					
7a	China PR	%	12.86	7.18	51.29	36.21
7b	Germany	%	5.91	3.81	9.39	9.61
7c	Saudi Arabia	%	80.90	88.34	38.13	53.08
7d	Share of Subject Countries	%	99.67	99.33	98.81	98.90
7e	Share of Other Countries	%	0.33	0.67	1.19	1.10
7f	Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

42. It is seen that:

- i. Imports of the subject goods from subject countries are significant and have increased in absolute terms during the POI as compared to the base year.
- ii. The data submitted by the DI and as obtained from DGCI&S, both exhibit increased imports, however, the DGCI&S data shows a gradual increase as compared to the drastic increase shown in the data from secondary source.

III. PRICE EFFECT

43. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to analyze whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course. The impact on the prices of the domestic industry on

account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. PRICE UNDERCUTTING

44. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed value of imports with net sales realization of the domestic industry.

S.N.	Particulars	Landed value	NSR of DI	Price undercutting		
		Rs./Kg	Rs./Kg	Rs./Kg	%	Range
1	China PR	56.66	***	***	***	1 -10
2	Germany	54.75	***	***	***	5 - 15
3	Saudi Arabia	54.51	***	***	***	5 - 15
4	Subject Countries	55.06	***	***	***	5 - 15

45. It is seen that the price undercutting for China PR, Germany and Saudi Arabia is positive.

ii. PRICE UNDERSELLING

46. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed value of imports.

S.N.	Particulars	NIP	Landed Value	Injury Margin		
		Rs./Kg	Rs./Kg	Rs./Kg	%	Range
1	China PR	***	56.66	***	***	10-20
2	Germany	***	54.75	***	***	15-25
3	Saudi Arabia	***	54.51	***	***	15-25
4	Subject Countries	***	55.06	***	***	15-25

47. It is seen that the landed value of the subject goods from subject countries were lower than the NIP determined for the domestic industry.

iii. PRICE SUPPRESSION/DEPRESSION

48. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Landed Value of imports	Rs./Kg	61.58	52.31	50.68	55.06
1a	Trend	<i>Indexed</i>	100	85	82	89
2	Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
2a	Trend	<i>Indexed</i>	100	85	70	69

3	Domestic Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
3a	Trend	<i>Indexed</i>	100	95	94	101

49. The above data demonstrates that the cost of sales of the domestic industry were very high in the base year which have declined consistently whereas the domestic industry has managed to keep the selling price at the same level during the entire injury period and the POI. It indicates that the prices of the Domestic Industry are not suppressed and depressed because of the alleged dumped imports.

IV. ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

50. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

i. MARKET SHARE

51. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Domestic Industry	%	1.03	6.29	8.00	15.45
2	Other Indian Producers	%	-	-	-	-
3	Imports from Subject Countries	%	97.61	92.28	91.09	83.94
4	Imports from Other Countries	%	1.36	1.43	0.91	0.61
5	Imports from subject countries relative to Indian consumption	%	97.61	92.28	91.09	83.94
6	Imports from subject countries relative to production of DI	%	***	***	***	***
6a	Trend	Indexed	100	37	23	12

52. It is seen that the market share of domestic industry has increased throughout the injury period and the POI whereas the share of imports from subject countries has decreased during the same period. The share of imports from other countries has remained at insignificant levels.

53. The above data demonstrates that the Domestic Industry being the sole producer of the subject goods has been able to increase its share in the market and the share of the imports has decreased. However, the DI's share is only about 15.45% and 84% of the Indian demand is still held by the subject countries.

54. Imports from subject countries in relation to domestic consumption / demand have declined during the entire injury period and the POI though it is still significant.

ii. CAPACITY, PRODUCTION, CAPACITY UTILIZATION AND SALES

55. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Installed Capacity	MT	30,000	30,000	30,000	30,000
2	Production	MT	701	2,095	3,901	7,035

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
3	Capacity Utilization	%	2.34	6.98	13.00	23.45
4	Sales of DI		305	2,260	3,535	6,712
4a	Domestic Sales	MT	305	2,182	3,239	6,533
4b	Export Sales	MT	-	***	***	***
4b(i)	Trend	Indexed	-	100	375	227

56. It is seen that the production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased over the entire injury period and POI. The export sales of the domestic industry have also increased during 2015-16 and 2016-17, however the same declined during the POI.

iii. PROFITABILITY

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Profit / (Loss)	Rs./Lakhs	(***)	(***)	(***)	***
1a	Trend	<i>Indexed</i>	(100)	(415)	(89)	313
2	Profit / (Loss)	Rs./Kg	(***)	(***)	(***)	***
2a	Trend	<i>Indexed</i>	(100)	(58)	(8)	15
3	ROCE	%	(***)	(***)	(***)	***
3a	ROCE	Range %	(0-5)	(5-10)	(0-5)	5-10

57. It is noted that the domestic industry has increased its profits to a significant level and became positive during the POI. The ROCE has also registered significant improvement and became positive during the POI.

58. It is stated by the domestic industry that the profits achieved in the POI is not of reasonable levels and the domestic industry could have achieved better profits had there been no price undercutting /suppression effects triggered by dumped imports. For ROCE the domestic industry claimed that they have not been able to earn an adequate return on capital employed throughout the injury investigation period though the situation was positive during the POI.

iv. INVENTORIES

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	158	208	244

59. It is seen that the average inventory with the domestic industry has increased throughout the injury period and the POI, however in view of the absence of data regarding average permissible inventory levels, the impact of increased inventory cannot be gauged.

v. PRODUCTIVITY OF THE DOMESTIC INDUSTRY

S.N.	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
1a	<i>Indexed</i>	<i>Index</i>	100	117	117	350
2	Productivity per Employee	MT/ Employee	***	***	***	***
2a	<i>Indexed</i>	<i>Index</i>	100	256	477	287

60. It is seen that the employment level of the domestic industry has shown similar trends as that of production and increased in the injury period and POI. Further, productivity per employee also has improved.

vi. ABILITY TO RAISE CAPITAL INVESTMENTS

61. It was submitted by the petitioner that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made significant investments in plant and machinery and set up capacity to the tune of 30,000 MT against a demand of about 42,000 MT. However, despite these investments and demand, the highest capacity utilization achieved by the domestic industry was about 24% that too during the POI. Thus, the question of further investment at this stage may not be significant. However, the petitioners submitted that the ROCE currently achieved by them are not reasonable and any further investment shall depend on the sustainability of investments already made.

vii. LEVEL OF DUMPING & DUMPING MARGIN

62. It is noted that imports from the subject countries are entering into the country at dumped prices and that the margins of dumping is positive.

viii. GROWTH

63. From the information provided by the domestic industry it is seen that the growth has shown multifold increase in respect of capacity utilization, production and sales. Further the selling price, profits, ROI etc have also shown positive growth.

ix. FACTORS AFFECTING DOMESTIC PRICES

64. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc., shows that the landed value of imported goods from the subject countries is below the non-injurious price and selling price of the domestic industry, causing a positive price under-cutting and price under selling in the Indian market. However, the net sales realization of DI has consistently been above the landed value of subject goods from the subject countries despite its nominal share in country's demand of PUC.

65. It is seen that there has been an increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms though the same decreased in relation to consumption and production of the product in India. Though the production and sales by the domestic increased over the years, the market share of the dumped imports remained at about 84% in the POI and the domestic industry was operating only at 24% capacity utilization. Dumped imports have had some adverse price effect in terms of price under-cutting and price under-selling. However, the net sales realization of DI has remained about 8 to 11% above the landed prices. As a result, the profits and ROCE achieved by the domestic industry during the injury period have shown improvement and was positive during POI.

V. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

66. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

S.N.	Producer/ Exporter	NIP	LV	IM		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd China PR	***	***	***	***	5-15
2	Luxi Chemical Group Chor alkali chemical branch /Shandong liaocheng Luxi new material sale co. ltd / Luxi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd, China PR	***	***	***	***	15-25

3	Methanol Chemicals Company, Saudi Arabia	***	***	***	***	15-25
4	Germany	***	***	***	***	15-25

H. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

67. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Rules and Agreement on Anti-dumping, the Authority proceeded to see whether any factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

i. Imports from Third Country

68. The imports from countries other than subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. About 99% of total imports during the POI are from subject countries.

ii. Contraction in demand

69. The demand for the subject goods has shown an increasing trend in absolute terms. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry. The share of DI during the entire injury period has remained consistent.

iii. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

70. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have impacted the DI.

iv. Developments in technology

71. The technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology had no impact on the growth of the DI.

v. Changes in pattern of consumption

72. The DI is producing similar goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused any impact on the DI.

vi. Export performance

73. The DI has exported the goods from 2015-16 onwards, however, the domestic sales only have been identified and examined for the present analysis.

vii. Performance of the domestic industry with respect to other products

74. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the DI has not impacted the DI as the information with respect to the product under consideration only has been considered for analysis.

viii. Productivity of the domestic industry

75. The Authority notes that the production and productivity of DI has shown steep improvement when compared from base year to the subsequent years in the injury period and POI.

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

76. The post disclosure submissions have been summarized and addressed as below:

Views of the Domestic industry

77. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The decision to use Export Genius data was purely on account of unavailability of DGCI&S T/T data at the time of filing of petition and the petitioner has never tried to show any fabricated situation of import or injury before the Authority by relying on a secondary source import data or in any other

manner. The petitioner did not submit secondary source data as a conclusive one but used the said data as the most reliable one with the given facts at that juncture.

- ii. A higher level of imports as per DGCI&S T/T data no way puts the claims of injury in the petition made by petitioner under doubts.
- iii. Dumping margin even from the responding exporters is very significant. Thus, the claims of dumping by the petitioner stands established.
- iv. It is humbly requested that Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd should not be granted any individual margin if they have only exported very low or a non commercial volume during the POI. Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd was not a major exporter of DMF to India. This company have the potential to export much more and it is apparent that the price of this exporter has already started to come down.
- v. The factual disclosure of injury parameters shows the DI suffered material injury and we request the Authority to conclude that the DI has suffered material injury. Though the sales of the DI increased along with increases in demand, the presence of dumped imports at very high level. The profitability and ROCE situation of the DI also showed a below par performance and situation of material injury.
- vi. There seems some calculation error in the Allowable return. The return calculated by the Authority is not correct.

Views of the opposing interested parties

78. The submissions of various opposing interested parties are summarized as follows:

- i. The domestic industry did not provide the accurate and adequate information in the current investigation at the time of initiation, it is in itself a sufficient ground for the termination of the current investigation.
- ii. It is requested to determine the normal value for the Chinese exporters on the basis of their records but not on the basis of constructed normal value. It is requested to consider the information from Saudi Arabia for the determination of normal value for the Chinese exporter in the current investigation.
- iii. Normal Value of Chemanol should be determined in accordance with the procedure in Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975. The DA has not disclosed any instance or recorded any fact which states that Chemanol has provided an incomplete questionnaire response or insufficient information which did not allow for the determination of normal value as per the residuary methods of construction provided under Section 9A(1)(c)(ii)(a) and 9A(1)(c)(ii)(b). The present methodology adopted by the DA for determination of Normal Value by resorting to best facts available and thereby, using the cost of production of the Domestic Industry is clearly in derogation of the statutory scheme and unsustainable.
- iv. The best fact available applied against Chemanol have not been disclosed depriving Chemanol of the opportunity to comment on the same.
- v. The Normal Value considered on the basis of cost of production of the Domestic industry is not appropriate as the domestic industry's cost of production is highly distorted due to capacity utilization of only 23%, which has inflated its cost of production.
- vi. There is a significant variance in the export prices on monthly and quarterly basis in the POI for the exporter of Luxi Group.
- vii. The consumption norms of the petitioner or the conversion cost in the POI was abnormally high due to low plant utilisation. The same cannot be used for determining normal value for the foreign producers who are operating the plants at much different level of capacity utilisation.
- viii. No material injury suffered by Domestic Industry as all relevant economic parameters show significant improvement. An overall analysis of the economic parameters set out in para (iv) of Annexure II clearly reveal that the situation of the Domestic Industry improved substantially and that imports from the subject countries have had no impact on its performance. In case the DA is of the opinion that only the existence of a dumping margin demonstrates material injury to the Domestic

Industry, then cogent reasons must be furnished on why the presence of only the dumping margin outweighs the positives that have been witnessed in the other 14 parameters.

- ix. The Domestic Industry has cherry picked the source of import data with the motive of prejudicing the DA by portraying a 196% increase in imports whereas the actual increase in imports as per DGCI&S data was merely 23% from that of the base year and pertinently, imports actually decreased by 5% in the POI from that of the year immediately preceding it i.e. 2016-17.
- x. DI sales are disproportionately higher as compared to increase in imports. If imports have still remained significant, it is only because of demand-supply gap in the Country.
- xi. The price effect of subject imports on the domestic market of the like article is absent.
- xii. Price undercutting and price underselling are not the factors of injury as has been laid down by the Hon'ble CESTAT in the case of *Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.)*. Price underselling is an irrelevant factor as far as determination of injury to the Domestic Industry is concerned. The reasons for the positive price undercutting is high price targeted by the petitioner.
- xiii. No causal link can be established as no injury suffered by the Domestic Industry.
- xiv. There is no merit in the submissions of the domestic industry for earning reasonable profits and ROCE.
- xv. There are other factors impacting the domestic industry and preventing it from reaching optimum capacity utilization.
- xvi. The domestic industry being multi-product company and making profits, its ability to raise funds has not been affected by the performance of the newly introduced subject goods.
- xvii. The petitioner has recently commenced production and the best utilization achieved by the domestic industry stands at 23%, it would be grossly inappropriate to determine the NIP at such low levels of capacity utilization.

Examination by the Authority

79. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs.

J. CONCLUSIONS

80. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts available, as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i. The volume of PUC exported to India from Saudi Arabia is consistent and quite large over the entire injury period, whereas volume from Germany is not very large though consistent. Volume of exports from China PR have declined during POI.
- ii. The large volume of imports are in response to the increased demand in the country and are not directly impacting the DI as is reflected by the positive growth in DI's performance.
- iii. There is overall improvement in the health of the domestic industry. The production from base year (2014-15) to subsequent years have multiplied manifold and during POI has reached 10 times of the production of the base year. The sales of DI have also shown multifold increase.
- iv. The evident positive growth of DI is inspite of the fact that during the same period, the imports have been substantial to the extent of 97% of the Indian consumption which have declined to 83.9% though they are still substantial in absolute terms.
- v. The analysis of economic parameters indicate that injury to the domestic industry cannot be attributed to the alleged dumped imports. Hence, it is concluded that there is insufficient evidence to establish that alleged dumping is resulting in material injury to the domestic industry.

K. RECOMMENDATION

81. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic producers, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the present investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules it is established that the domestic industry is not suffering injury on account of the subject imports from the subject countries and there is no causal link between the dumped imports material injury to the domestic industry due to reasons given above. The Authority is of the view that imposition of antidumping duty is not warranted in the present investigation. In view thereof the Designated Authority considers it appropriate to not recommend Anti-Dumping Duty in respect of 'Di Methyl Formamide' (DMF) from China PR, Saudi Arabia and Germany into India.

82. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision on Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority W.P. (Civil) No. 8202/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General